www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित | हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 01 | गोरखपुर, 30 जून, 2024 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

विपक्ष की मजबूत आवाज बनेंगे राहुल गांधी

राहुल गांधी सदन में विपक्ष की मजबूत आवाज बनकर उभरेंगे, इसमें सन्देह नहीं है। पक्ष एवं विपक्ष के बीच एक संतुलन बनना लोकतंत्र की खूबसूरती है एवं अपेक्षा भी है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में विपक्ष के नेता की प्रमुख भूमिकाओं में से एक सरकार की नीतियों पर ह्यप्रभावीह्न सवाल उठाना है। विपक्ष के नेता की भूमिका वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि उसे सरकार की विधायिका और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करनी होती है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें सरकारी प्रस्तावों-नीतियों के विकल्प प्रस्तुत करने होते हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष अलग एवं ऊंचे स्तर पर अपने तेवर दिखा सकता है। सरकार के लिए कोई भी बिल पास कराना अब इतना आसान नहीं होगा। मोदी की स्थिर सरकार देने की जद्दोजहद के बीच मोदी और राहुल के बीच की टकराव की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके सदन में सकारात्मक वातावरण बना रहना भी जरूरी है। स्थिर सरकार देश की बड़ी जरूरत है, राजनेताओं से उम्मीद की जाती है कि एक बार जनादेश आने के बाद वे चुनावी दौर की कड़वाहट एवं आरोप-प्रत्यारोप की छिछालेदार राजनीति को भुलाते हुए जनता के हित में मिलकर काम करें। इस बार भी चुनाव में अपनी-अपनी पार्टियों के प्रचार की अगुआई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने एक-दूसरे पर खूब हमले बोले हैं। अब उन बातों को पीछे छोड़ते हुए उन्हें बेहतर तालमेल वाले कामकाजी रिश्ते कायम करते हुए देशहित को सामने रखना होगा। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना होगा।

राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बन गये हैं, यह उनका पहला संवैधानिक पद है, इससे पहले वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इस बड़े पद के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जायेंगी। दस वर्षों बाद लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद मिला है। वैसे इस बार के चुनाव एवं चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद राहुल गांधी का न केवल आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि उनमें राजनीतिक कौशल एवं परिपक्वता भी देखने को मिल रही है, इससे यह प्रतीत होता है कि वे प्रतिपक्ष नेता के पद के साथ न्याय करते हुए अपनी राजनीति को चमकायेंगे एवं रसातल में जा चुकी कांग्रेस को सुदृढ़ करेंगे। वैसे देखा गया है कि प्रतिपक्ष के नेता बनने वाले अधिकांश लोग प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं। लेकिन राहुल गांधी को इसके लिये अभी लम्बा संघर्ष करना होगा, परिपक्व राजनीति एवं देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को साबित करना होगा।

निश्चित ही राहुल गांधी का कद बढ़ा है और अब वे स्वल्प समय में ही कद्दावर नेता की तरह राजनीति करने लगे हैं। राहुल को देशभर में निकाली यात्राओं एवं चुनाव प्रचार में निभाई सशक्त भूमिका ने मजबूती दी है।

जातीय आरक्षण के नर्क से देश को निकालने में मदद करें कोर्ट

हाल ही में हाईकोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार तेजश्वी यादव के उस कूटरचित कार्य की हवा निकाल दी जिसमें जाति विशेष का वोट प्राप्त करने के लिए ओबीसी आरक्षण को 65% कर दिया था। अब जातीय आरक्षण की आग से जल रहे देश को बचाना है तो कोर्ट को आगे आना होगा। जो दलित ओबीसी या एससी एसटी सीट पर मंत्री, विधायक या सांसद बन जाते है उन्हें पांच साल वीआईपी जीवन मिल जाता है और फिर जब वापिस चुनाव आता है तों वो फिर दलित दबे कुचले की श्रेणी में खड़े होकर वापिस चुनाव में आरक्षण का लाभ ले लेते है ठीक ऐसे ही किसी दलित या ओबीसी को यदि सरकारी नौकरी मिल जाती है तों भी उसके बेटे बेटी गरीब दबे कुचले ही माने जाते है। यह खुली विसंगति है, अन्याय है जिसके विरुद्ध अब सभी को सरकार के समक्ष खड़ा होना चाहिए। मेरा तो मानना है कि देश के सारे सरकारी प्राइमरी स्कूल भी निजी क्षेत्र में दे दिए जाने चाहिए। वैसे भी इन सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चे पढ़ने के लिए नहीं भेजते। कुछ गरीब अपने बच्चे सिर्फ मध्यान्ह भोजन के लिए भेजते हैं। सारा जोर भोजन पर है। तो सिर्फ रसोइया रखिए। इतने सारे अध्यापक रखने कई क्या जरुरत है। मिसाल के लिए आप बिहार को देखिए। बिहार बोर्ड क्या पैदा करता है, गणेश और रूबी राय जैसे फर्जी टापर। लेकिन उसी बिहार में आनंद का कोचिंग आई आई टी में अपने सारे बच्चे भेज देता है। बिहार के एक गांव के बच्चे भी आगे आए हैं। तो क्या सरकारी स्कूलों के भरोसे ? देश के सारे प्राइमरी स्कूल हाथी के दांत बन कर सिर्फ हमारे टैक्स का पैसा चबा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी शून्य है। आप मत मानिए और मुझे लाख गालियां दीजिए, यह कहने के लिए, लेकिन कृपया मुझे कहने दीजिए कि जातीय आरक्षण ने देश में विकास के पहिए में जंग लगा दिया है। बस सेवाओं का निजीकरण करते समय नियामक संस्थाओं को कड़ा बनाए रखना बहुत जरुरी है। आप सोचिए कि स्कूल अस्पताल आदि प्राइवेट सेक्टर में न होते तो क्या होता। इन सभी सरकारी सेवाओं, स्कूलों में दुर्गति का बड़ा कारण आरक्षण है। सोचिए यह भी कि अगर प्राईवेट सेक्टर नहीं होता तो सवर्णों के बच्चे कहां पढ़ते और कहां नौकरी करते। तो क्या यह देश अब सिर्फ आरक्षण वर्ग के लोगों के लिए ही है। यह देश सभी समाज, सभी वर्ग के लिए है। पर दुनिया का इकलौता देश भारत है जहां पचास प्रतिशत से अधिक आरक्षण है और अब सर्वदा के लिए है। यही हाल देश के सारे सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटरों का भी है। यहां डाक्टर सिर्फ वेतन लेते हैं, इलाज नहीं देते। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ सरकार के भरोसे रहे तो क्या कहीं कोई आ जा पाएगा ? जातीय आरक्षण ने सिर्फ समाज में ही आग नहीं लगाया है, देश के विकास को भी भाड़ में डाल दिया है। आप चले जाईए किसी सरकारी आफिस में। और किसी आरक्षित वर्ग के किसी अधिकारी, कर्मचारी से करवा लीजिए कोई काम नहीं होता, कुछ भी हो लेकिन काम नहीं होगा। बिना रिश्वत के नहीं होगा। पूछ लीजिए किसी सवर्ण अधिकारी या कर्मचारी से कि क्या वह आरक्षण समुदाय के लोगों से काम ले पाता है ? या यह लोग काम जानते भी हैं ? जानते भी हैं तो क्या करते भी हैं ? बहुत सारे सवाल हैं जो हर सरकार में अनुत्तरित हैं। बस एक यह कि निजीकरण में संस्थाएं लूट का अड्डा नहीं बनें। उन पर पूरी सख्ती रहे। यकीन मानिए अगर ऐसा हो गया तो यह जो जातियां आरक्षण के नाम पर, उस की मांग में आए दिन देश जलाती रहती हैं, यहां वहां आग लगा कर देश की अनमोल संपत्ति नष्ट करती रहती हैं, इन पर भी अपने आप लगाम लग जाएगी। जब सब जगह प्रतिद्वंद्विता आ जाएगी तो यह लोग आरक्षण मांगना, अरे आरक्षण शब्द भूल जाएंगे। नहीं, यह लोग आरक्षण के नाम पर ऐसे ही देश को ब्लैकमेल करते रहेंगे, देश जलाते रहेंगे। और मुफ्त की मलाई काटते रहेंगे। उठिए और जागिए। देश को तरक्की के रास्ते पर ले चलने का सपना देखिए।

पंकज सीबी मिश्रा,
जौनपुर यूपी

इतिहास में जो कुछ हुआ, उसे अब खत्म किया जाना चाहिए

लोहिया इस बात को बखूबी समझते थे कि भारतीय समाज में 'जाति' एक महत्वपूर्ण कारक है। जो लोग इसे सैद्धांतिक रूप से नहीं मानते हैं, वे इसे व्यावहारिक तौर पर इसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने लिखा कि भारत में 'जन्म, मृत्यु, विवाह, दावत जैसे अनेक अनुष्ठान' जातिगत ढांचे के अनुसार ही चलते हैं। इस व्यवस्था को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था कि ₹ऊंची जातियों के लोग राजनीतिक और आर्थिक, दोनों तरह से अपना शासन बनाए रखें। वे अकेले इस व्यवस्था को बंदूक के दम पर नहीं चला सकते थे, इसलिए उन्हें उन लोगों में हीनता की भावना को भरना था, जिन पर वे राज करना चाहते थे या जिनका शोषण करना चाहते थे।

यद्यपि लोहिया दलितों के विरुद्ध भेदभाव को नजरअंदाज नहीं करते। उनका ध्यान उन सवर्ण या उच्च जातियों पर केंद्रित है, जहां से राजनीतिक, प्रशासनिक, पेशेवर, व्यावसायिक और बौद्धिक अभिजात्य वर्ग आते थे और छोटी जातियों का सत्ता और उच्च पदों पर बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व नहीं था। 1958 में उन्होंने लिखा था कि सवर्ण, भारत की आबादी के पांचवें हिस्से से भी कम हैं। इसके बाद भी वे राष्ट्रीय गतिविधियों, व्यापार, सेना, सिविल सर्विस या फिर राजनीतिक पार्टियों में आसानी से आ जाते हैं। राष्ट्र की प्रगति के लिए इस असंतुलन को सही करना होगा। लोहिया चाहते थे कि उनके साथी समाज के निचले वर्गों, जैसे कि महिलाओं, पिछड़ों, हरिजन, मुस्लिम और आदिवासियों को ऊपर लाने के लिए संघर्ष करें, भले ही उनकी योग्यता आवश्यक रूप से कम हो। वे मानते थे कि सदियों पुराने इतिहास में जो कुछ हुआ, उसे अब खत्म किया जाना चाहिए।

ब्रिटिश शासन के अंतिम दशकों की बात करें तो भारत में समाजवादी और कम्युनिस्ट नेता उपनिवेशवाद विरोधी राजनीति में सक्रिय थे। उसके बाद आजादी के पहले के दशकों में ये दोनों गुट कांग्रेस पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बने रहे। समाजवादियों और कम्युनिस्टों की शुरूआती पीढ़ियों में साहस और आदर्श के अलावा दूसरे कई गुण भी थे। फिर भी उनमें एक कमी थी- भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव के बारे में जागरूकता की कमी। लेकिन इस मामले में समाजवादी विचारक और राजनीतिज्ञ राम मनोहर लोहिया एक अपवाद थे।

जातिगत भेदभाव के ऊपर लोहिया ने जो लिखा, उसे प्रशंसकों ने इकट्ठा कर उनके जीवनकाल में ही एक किताब के रूप में हैदराबाद से प्रकाशित कराया था। हालांकि वह किताब लंबे समय से अब प्रिंट में नहीं है, लेकिन एक स्वतंत्र प्रकाशक ने उसका संशोधित संस्करण जरूर निकाला। संयोग की बात यह है कि वह प्रकाशन संस्थान भी हैदराबाद में ही स्थित था। लोहिया ने अपने वामपंथी साथियों के बारे में लिखा था कि वे ईमानदारी से, लेकिन गलत तरीके से यह सोचते हैं। वे मानते हैं कि सिर्फ आर्थिक असमानता को खत्म करने के परिणामस्वरूप जातिगत असमानता अपने आप खत्म हो जाएगी। उन्हें आर्थिक और जातिगत असमानता रूपी राक्षस को खत्म करना था, पर वे इसे समझ पाने में असफल रहे।

6 दिसंबर, 1956 को आंबेडकर का निधन हो गया। लोहिया ने अपने साथी समाजवादी मधु लिमये को लिखा, आंबेडकर भारतीय राजनीति के महान व्यक्ति थे। गांधी के साथ-साथ वे भी सबसे बड़े हिंदू थे। इस तथ्य ने मुझे हमेशा से एक संबल और विश्वास दिया है कि हिंदू धर्म से जाति व्यवस्था एक दिन खत्म हो सकती है।₹ उन्होंने आगे लिखा, ₹डॉ. आंबेडकर विद्वान, ईमानदार, साहसी और स्वतंत्र व्यक्ति थे। उन्हें बाहरी दुनिया में ईमानदार भारत के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता था। लेकिन वे थोड़े सख्त थे। उन्होंने गैर-हरिजन का नेता बनने से मना कर दिया।

लोहिया ने सोचा कि आंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्हें डॉ. आंबेडकर ही बना रहने दिया जाए। जातिगत भेदभाव के प्रति लोहिया की गहरी जागरूकता उन्हें अपने समय के अन्य समाजवादियों से अलग करती है और यही बात उनके 'नारीवाद' पर भी लागू होती है। वे लिखते हैं, अगर भारतीय लोग पृथ्वी पर सबसे दुखी हैं, तो जातिगत भेदभाव और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण इस पतन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। लोहिया ने लिखा है, ₹एक पितृसत्तात्मक समाज में ऐसा होता है कि महिला का स्थान रसोई में है। ऐसे में समाजवादियों को इस बात का विरोध करते हुए कहना चाहिए कि ऐसे में तो पुरुषों की जगह नर्सरी में होनी चाहिए। साठ सालों से यह तर्क दिया जा रहा है कि बच्चों के पालन- पोषण में पति और पिता को बराबरी के साथ हिस्सा लेना चाहिए। यह एक आदर्श स्थिति हो सकती है, लेकिन व्यवहार में ऐसा कहीं दिखता नहीं।'

इस कॉलम में उद्धृत लेख, पत्र और भाषण 1953 और 1961 के बीच लिखे गए थे। ऐसा हो सकता है कि अभी ब्राह्मणवाद राजनीति और प्रशासन पर उतना हावी न हो, जितना 1950 के दशक में था। फिर भी संस्कृति और आर्थिक जीवन में वे आबादी में अपने हिस्से के अनुपात से कहीं ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इसलिए कई मामलों में जाति पर लोहिया के विचार और शब्द एक अद्भुत समकालीनता रखते हैं।

समाजवादियों से लोहिया की अपेक्षा थी कि वे अंतरजातीय, खासतौर से अलग-अलग वर्णों के बीच होने वाले विवाह को बढ़ावा दें। वे लिखते हैं, अगर जाति के बंधन को तोड़ दिया जाए या उसमें थोड़ी ढील दी जाए तो उच्च जाति के बहुत से युवा पिछड़ी जातियों की महिलाओं की ओर आकर्षित होंगे और अपने साथ-साथ देश के लिए खुशियां लाएंगे। ठीक इसी तरह पिछड़ी जातियों के लड़के उच्च जातियों की महिलाओं की जिंदगी में प्रवेश कर सकेंगे।

1960 में लोहिया ने जाति के अध्ययन और पिछड़ेपन को समझने के लिए संघ के गठन की बात कही थी। उन्होंने इस संघ के आठ मुख्य उद्देश्य बताए, जिनमें से दो के बारे में बताता हूं। पहला यह कि धर्म के साथ-साथ उसकी प्रथाओं को भी जाति दोष से मुक्त किया जाए, इस विश्वास के साथ कि अंतरजातीय विवाह करने से जातियां खत्म हो सकती हैं। दूसरा यह कि सरकारी पदों, राजनीतिक दलों, व्यापार और सशस्त्र सेवा में कानून या परंपरा के तौर पर 60 प्रतिशत पदों को पिछड़ी जाति, महिलाओं, हरिजन और आदिवासियों के लिए सुरक्षित करने की मांग की जाए।

पुस्तक के एक दिलचस्प हिस्से में 1955-56 में एक तरफ डॉ. लोहिया और उनके सहयोगियों तथा दूसरी तरफ डॉ. भीमराव आंबेडकर के बीच आदान- प्रदान किए गए पत्रों की एक श्रृंखला को पुनः प्रस्तुत किया गया है। यहां इन दोनों नेताओं और उनके अनुयायियों को एक-दूसरे के करीब लाने का प्रयास किया गया था, शायद इस उद्देश्य से कि उनकी दोनों पार्टियां 1957 के आम चुनावों में एक साझा मंच पर लड़ें। लोहिया और आंबेडकर के बीच जब पत्र- व्यवहार की शुरूआत हुई थी, लोहिया ने आंबेडकर से कहा था, ₹मैं चाहता हूं कि सहानुभूति के साथ गुस्सा भी जुड़ जाए और आप न सिर्फ पिछड़ी जातियों के, बल्कि भारतीय लोगों के भी नेता बनें।₹ आंबेडकर ने लोहिया के पत्र का जवाब देते हुए लिखा, ₹आप मुझसे 2 अक्तूबर को दिल्ली में आकर मिलें।₹ यह गांधी का जन्मदिन था और शायद यह महज एक संयोग था। दुर्भाग्य से लोहिया के घुमक्कड़ जीवन और आंबेडकर के खराब स्वास्थ्य के कारण दोनों क्रांतिकारी सुधारक व्यक्तिगत रूप से मिलकर संभावित सहयोग पर चर्चा नहीं कर पाए।

आसान नहीं होगा नए कानूनों का क्रियान्वयन

विशेषज्ञों की अलग-अलग राय के बावजूद नये कानूनोंका क्रियान्वयन आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकारके बुनियादी ढांचेका निर्माण, हितधारकोंको प्रशिक्षण प्रदान करना, नियम और संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित करना, मानक प्रपत्रों में संशोधन करना और परिचालन संबंधी मुद्दोंको सुलझानेके लिए अन्तर- एजेंसी समन्वय करना शामिल है। साथ ही एक बात जो विश्वास दिलाती है कि ये कानून समयपर लागू होंगे यह है कि एक अनुभवी और समय-परीक्षणित आपराधिक न्याय प्रणाली अस्तित्वमें है जिसमें किसी भी बदलावको अपनाने और सीमित संसाधनोंके साथ किसी भी समस्याका व्यावहारिक 'समाधान खोजने की कुव्वत है। नये कानून तय समयपर लागू होंगे, इसका एक और आश्वासन इस हकीकत से भी मिलता है कि पुलिस, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियोंको बड़े : पैमानेपर क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण दिया गया है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है। हालांकि कानून लागू करनेकी व्यवस्थासे जुड़े कुछ अधिकारी अब भी आशंकित हैं, उनका तर्क है कि नये कानूनोंके सफल प्रवर्तनसे सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रोंको अब भी सम्बोधित किया जाना बाकी है, ताकि अधिनियमोंका निर्वाध प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। बीएनएसएसमें कई अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं, जिसमें तलाशियों, जन्तियों और अपराधके दृश्यकी वीडियोग्राफी और केस प्रॉपर्टी आदिकी फोटोग्राफी शामिल हैं, जिनके लिए शुरूआत से ही इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल तकनीकीका प्रयोग करना आवश्यक होगा। हालात यह है कि सभी जांचकताओं और निर्णायकोंको अब भी उपयुक्त उपकरण और तकनीकी प्रदान करके उनका उपयोग करना सिखाना अभीतक सम्भव नहीं हो पाया है, ताकि आवश्यक डिजिटल आउटपुट समान रूपसे और स्वीकार्य रूप में उत्पन्न, सुरक्षित और संगृहीत किये जा सकें। इसके अतिरिक्त, ई-कोर्ट कार्यवाहीका संचालन और इलेक्ट्रॉनिक संचार आदिके माध्यमसे समन और वारंट भेजने सहित कई अन्य प्रक्रियाएं हैं, जिनके लिए अदालतों, पुलिस स्टेशनों और जेलोंका बड़े पैमानेपर डिजिटलीकरण, नियमोंका मानकीकरण, तकनीकी और सहायक कर्मचारियोंकी भर्ती और प्रशिक्षण, वित्तीय संसाधन और अंतर- एजेंसी समन्वय अति आवश्यक होंगे। जमीनी हकीकत यह है कि अभीतक अधिकांश राज्योंमें इस दिशामें कुछ भी ठोस नहीं किया गया है। बीएनएसमें दी गयी दंडकी सूची में सामुदायिक सेवाको भी शामिल कर लिया गया है, वस्तुस्थिति यह है कि एजेंसियोंको अभीतक इस सजाको लागू करनेके अधिकार क्षेत्रके बारेमें स्पष्ट जानकारी नहीं है, न ही इस सजाको भुगतानेके लिए आवश्यक संस्थानोंकी पहचान करके नियम बनाये गये है। नये कानूनोंसे सम्बन्धित प्रावधानोंको लागू करनेके लिए आवश्यक नियम अभावमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताके अनेक मुख्य प्रावधानों जैसे- गवाहोंकी सुरक्षा, आरोपितकी अनुपस्थितिमें मुकदमेकी काररवाई, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमसे सम्मन और वारंट भेजना, अपराध करके अर्जित की गयी सम्पत्तिको जब्त करके पीड़ितोंमें बांटना, माल मुकदमेका समयपर निबटान, अनुसंधान प्रक्रियाकी वीडियोग्राफी इत्यादिको लागू करना लगभग असम्भव होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन नियमोंको बनानेके लिए राज्योंको आवश्यक दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिये गये हैं। उपरोक्त परिस्थितियोंको ध्यानमें रखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि न्याय व्यवस्थाके सभी अंग अपने-अपने क्षेत्रमें पुनः उन क्षेत्रोंकी पहचान करें जिनमें क्रियान्वयनसे सम्बन्धित नियम और प्रोटोकोल बनाना नितान्त

आवश्यक है। तीन नये आपराधिक कानून, अर्थात भारतीय न्याय सहिता २०२३ (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ (बीएसए) १ जुलाई, २०२४ से लागू होने जा रहे हैं। भारतके मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चन्द्रचूड़ने आपराधिक प्रक्रियाको डिजिटल बनानेके उद्देश्यसे बनाये गये नये कानूनोंकी सराहना की है और उन्हें भारतीय न्याय प्रणालीके आधुनिकीकरणकी दिशामें एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जबकि कानूनी बिरादरीके एक वर्गने इन कानूनोंके कुछ प्रावधानोंकी अनिश्चितता, अस्पष्टता और संवैधानिकताके बारेमें गम्भीर चिंता जतायी है। ममता बनर्जी सहित विपक्षी राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि नये अधिनियमोंको तबतक स्थगित रखा जाना चाहिए जबतक कि लोकसभाके नवनिर्वाचित सदस्य उनकी संस्तुति नहीं कर देते। उनका तर्क है कि ये कानून संसदमें बिना किसी सार्थक बहसके जल्दबाजी में पारित कर दिये गये थे, क्योंकि अधिकांश विपक्षी सदस्य निलम्बित थे। नये आपराधिक कानूनों की वैधताके बारेमें इतनी देरीसे चिन्ता व्यक्त करना अवसरोंकों गंवानेके अलावा और कुछ नहीं है, ये कानून तीन सालकी लम्बी परामर्श प्रक्रिया और हितधारकोंके साथ व्यापक विचार-विमर्शके बाद बनाये गये थे। इसके बाद स्वराष्ट्र मंत्रालयकी संसदीय समिति द्वारा इन कानूनोंकी गहन जांच की गयी थी। यहांतक कि दो अलग-अलग अवसरोंपर सार्वजनिक नोटिसके जरिये जनतासे सुझाव भी मांगे गये थे। सरकार इनमें से किसी भी मांगके आगे नहीं झुक रही है और कानूनोंको लागू करनेके लिए दृढ़ संकल्पित दिख रही है। इसके अतिरिक्त, नये प्रावधानोंकी असंवैधानिकताके बारेमें चिंताएं इस तथ्यके मद्देनजर सही नहीं हैं कि बीएनएसमें बदलाव मुख्य रूपसे नवतेज जौहर (२०१८), जोसेफ शाइन (२०१८) और पी. रथिनम (१९९४) के मामलोंमें सुप्रीम कोर्टके निदेशोंका प्रतिबिम्ब है। भारतीय न्याय संहितासे राजद्रोहकी धारा हटाना राजद्रोह कानूनको चुनौती देनेवाली याचिकाके जवाब में शीर्ष अदालतमें केन्द्र सरकारके हलफनामेपर क्रियान्वयन दशार्ता है, साथ ही इसमें लम्बे समयसे लम्बित राष्ट्रीय सुरक्षाके मुद्दोंको भी सम्बोधित किया गया है। बीएनएसएस और बीएसए में संशोधनोंपर आपत्तियां भी उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इनके मूल रूपसे आपराधिक काररवाईका डिजिटलीकरण और पीड़ित तथा नागरिकोंकी अपेक्षाओंके अनुरूप प्रावधानोंको शामिल करना है। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण जांच और त्वरित न्यायकी मांगको पूरा करनेके लिए आपराधिक प्रक्रियाओंको फिरसे स्थापित किया गया है। व्यापक पैमानेपर तकनीकी, कानूनी एवं अन्य सहायक कर्मचारियों और अधिकारियोंकी नियुक्ति तथा प्रशिक्षण एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिसे अब और लम्बित नहीं रखा जा सकता। अपराध एवं अपराधियोंपर निगरानी रखनेके लिए नेटवर्क (सीसीटीएनएस) तथा न्याय-व्यवस्थासे जुड़ी हुई संस्थाओंके बीच समन्वयक 3 सॉफ्टवेयरका उन्नयन और आधुनिकीकरण अभीतक पूरा नहीं हो सका है। यह जानना जरूरी हो जाता है कि यह कार्य राज्य स्वयंमें पूरा करनेके लिए सक्षम नहीं है। इसके लिए राज्योंको केंन्द्र सरकारकी एजेंसियोंसे आवश्यक तकनीकी सॉफ्टवेयर तथा मार्गदर्शनकी दरकार होगी। निःसंदेह नये कानूनोंको लागू करनेके पथमें राज्य सरकारोंका आगे बढ़ना बिना केन्द्र सरकारके सहयोग और सहारेके चलना सम्भव नहीं होगा। कदम-कदमपर राज्योंको केन्द्र सरकारकी मददकी जरूरत होगी। नये आपराधिक कानूनोंको लागू करनेके साथ केन्द्र सरकारकी निष्ठा और तत्परता भी जुड़ी हुई है, अतः केन्द्रीय एजेंसियोंको चाहिए कि राज्य सरकारोंके साथ कन्धेसे कन्धा मिलाकर काम करें ताकि इन कानूनों को समयबद्ध और सुचारु रूपसे लागू किया जा सके।

पेपर लीक होना शत- प्रतिशत भ्रष्ट व्यवस्था का नतीजा

मोदी सरकार ने परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले बेईमान लोगों को सबक सिखाने के लिए लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 अमल में ला दिया है। यह कानून परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने में कितना कामयाब होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन सवाल यही है कि हमारे नीति-नियंता आब तक आखिर क्यों नौजवानों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ पर आंखें मूंदकर बैठे थे ? अगर इस तरह के प्रयास पहले किए जाते, तो संभवतः नीट और नेट के परीक्षार्थियों की जो गत हुई, वह नहीं होती। वैसे, यह भी कम अफ़सोस की बात नहीं कि आज देश में ज्यादातर लोग परदे के पीछे से सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। वे अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करके डिग्री हासिल करते हैं व नौकरी पाना चाहते हैं। यह सब व्यवस्थागत दोष का नतीजा है। परीक्षाओं का पेपर लीक होना शत- प्रतिशत भ्रष्ट व्यवस्था का नतीजा है। यह भ्रष्टाचार निर्विवाद तौर पर राजनेताओं की

छत्रछाया में ही पनपा है। अगर सरकारो ने इस बीमारी का इलाज शुरू में ही करने की रुचि दिखाई होती, तो आज पेपर लीक नकल जैसी बीमारी मेहनतकश युवाओं के लिए मुसीबत नहीं बनती या इनके सुनहरे भविष्य के सपने को ध्वस्त न करती। इसलिए हमें व्यवस्था पर चोट करनी होगी। जब तक ऐसे गलत काम करने वाले सभी सरकारी अफसरों से लेकर निचले पदों के कर्मचारियों व राजनेताओं में नैतिकता की भावना का विकास नहीं होगा, तब तक कागज पर लिखे सख्त कानून ऐसी धोखाधड़ी को नहीं रोक सकते हैं। यह समझना होगा कि कानून तभी कामयाब होता है, जब उसके रखवाले खुद उस पर अमल करें । जब बाड ही खेत को खाने लग जाए तो उस खेत को तबाह होने से भला कौन रोक सकता है ? इसलिए पहले व्यवस्था में सुधारे होना चाहिए और यह कोई पंचवर्षीय योजना जैसी न हो, बल्कि त्वरित कारवाई की जाए। यहां मीडिया की भी उल्लेखनीय भूमिका है। वह इस मुद्दे को तब तक सुर्खियों में रखे, जब तक छात्रों को इंसाफ नहीं मिल जाता। प्रधानमंत्री दसवीं और बारहवीं की वार्षिक परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों का हौसला बढ़ाने के लिए परीक्षा पर चर्चा' करते हैं। ऐसी कवायद प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को परीक्षार्थियों का साथ देना चाहिए और उनको इंसाफ मिलने का पूरा भरोसा देना चाहिए । इससे व्यवस्थागत दोष जल्द ही दूर होने का विश्वास जगेगा, जो अंतरतः देश के लिए सुखद नतीजा लेकर आएगा। इन दिनों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पैपर लीक का मुद्दा गमार्या हुआ है। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षाओं में नकल और लीक रोकने केलिए जो नकल-रोधी कानून 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' बनाया, उसे प्रभावी कर दिया गया है। कानून का डर दिखाकर अपराध रोकने की यह कोशिश सराहनीय है, पर इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि कानून होने के भय मात्र से अपराध रुक जाएंगे। यह अपराध तभी रुकेगा, जब तंत्र पूरी तरह से ठीक होगा। मेरा मानना है कि हजारों-लाखों परीक्षार्थियों व बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को सखसजा मिलनी चाहिए। मुमकिन हो, तो फांसी की सजा का प्रावधन हो, ताकि वे अपराध करने से पहले हजार बार सोचें।

सवालों से घिरा पुलों का ढहना

आखिर कौन है जिम्मेदार ? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बिहार के अररिया में जो पुल ढह गया, उसका निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के तहत नहीं किया गया था। इसका काम बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत चल रहा था। सबके पास अपने-अपने बहाने हैं ? हर कोई जिम्मेदारी से बचना चाहता है ? हालांकि, मूलभूत ढांचा विकास के मोर्चे पर बिहार में सजगता का विस्तार होना चाहिए। कई जगह यह शिकायत आती है कि लोग ही पुलों को कमजोर करते हैं, तो कई जगह ठेकेदारों से रंगदारी मांगने की शिकायतें भी सामने आती हैं। हमें यह समझना होगा कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और संरक्षण के कार्य में समाज की भी भागीदारी है। समाज अगर सजग रहे, तो गुणवत्ता वाले पुलों का निर्माण सुनिश्चित हो सकता है और ऐसा ही होना चाहिए। शनिवार, 22 जून को सीवान जिले में जो पुल ढहा है, वह अपेक्षाकृत छोटा था और ढहते वक्त उसके नीचे बहुत तेजी से पानी -बह रहा था। अगर आसपास के लोग समय पर न देखते, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कहा जा रहा है कि यह पुल 30 साल पुराना हो चुका था। पूछा जा सकता है कि क्या समय-समय पर इसकी मरम्मत होती थी ? क्या मरम्मत से पुल के जीवन को बढ़ाया जा सकता था ? अगर पुल की मरम्मत मुमकिन नहीं थी, तो समय रहते उसके बगल में एक अन्य पुल का निर्माण हो जाना चाहिए था। आदर्श स्थिति तो यही है कि जो पुल पुराने पड़ चुके हैं, उनके समानांतर नए पुल का निर्माण समय रहते होना चाहिए। यह प्रशासन के लिए ही नहीं, स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के लिए भी शर्म की बात है कि पुल की स्थिति के प्रति उनकी सजगता उतनी नहीं है, जितनी होनी चाहिए। लोगों की सजगता से ही पुल बनते और मजबूत होते हैं। जहां के लोग सजग नहीं होते, वहां पुलों को ढहने से कोई रोक नहीं सकता। खैर, तीसरा पुल रविवार को मोतिहारी में गिरा है, जो अभी निमार्णाधीन था। यह बहुत दुख की बात है कि बारिश के मौसम में पुल टूट रहे हैं। बिहार में तमाम नदियां, नाले तेज बहेंगे, मजबूत पुलों की हर जगह जरूरत पड़ेगी अब जब सप्ताह भर में तीन पुल ढह चुके हैं, तो जाहिर है कि लोगों की चिंता बहुत बढ़ गई होगी।

बिहार में एक ही सप्ताह में तीन पुलों का ढहना जितना चिंताजनक, उतना ही निंदनीय भी है। तीनों पुल अलग-अलग प्रकार के हैं। एक पुल नया बना था, तो दूसरा पुराना हो चुका था और तीसरा तो अभी बन ही रहा था। अररिया में नवनिर्मित पुल करीब 180 मीटर लंबा था और जाहिर है, उसके निर्माण में गंभीर लापरवाही हुई है, इसलिए यह 18 जून मंगलवार को धूल में मिल गया। यह गहरे अफसोस और शर्म की भी बात है कि इस पुल का उद्घाटन तक नहीं हुआ था। इसे मलबे में बदलने में कुछ सेकंड लगे, पर वास्तव में पुल को मलबा बनाने की साजिश महीनों से चल रही होगी ? पुल बनाने वाले ठेकेदार अगर इस काम की विशेषज्ञता नहीं रखते थे, तब उन्हें काम क्यों दिया गया ? इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए। हो सकता है, ठेकेदार या निर्माण कंपनी की सीधे-सीधे गलती न हो, पर अगर गलती है, तो अक्षम्य है। कमजोर पुल किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकता है, जो भी ठेकेदार इंजीनियर और शासकीय अधिकारी कमजोर पुल बनाते या बनवाते हैं, उन पर जान लेने की साजिश का मुकदमा चलना चाहिए।

दास्तान-ए-सियासत

रंग बदलती राजनीति में दक्षिण की दिशा काबिलेगौर

तमिलनाडु में अंकतालिका में सिफर पर रहने का दुःख बीजेपी को अगले पाच साल सालता रहेगा। मोदी और शाह -3 की जोड़ी को तमिलनाडु से बड़ी उम्मीद थी और उन्होंने यहां कमल खिलाने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी थी। उन्हें अन्नामलै जैसा तुर्श नेता भी मिल गया, लेकिन द्रविड़ राजनीति के इस भूखंड में उसका सुर-ताल नहीं बदला, लिहाजा अन्नाद्रमुक से उसका गठबंधन टूट गया। बीजेपी ने इस अलगाव का खामियाजा भुगता।

धुर दक्षिण के दोनों राज्यों- तमिलनाडु और केरल के मतदाताओं ने कमाल कर दिया। दोनों की सोच यकसां रही और दोनों ने एनडीए को धता बता दी जीत के मान से नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिये पूर्णतः निराशाजनक रहे, अलबत्ता उसके वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ। तमिलनाडु में द्रमुकनीत गठबंधन के सामने अन्नाद्रमुक और बीजेपी समेत सभी का सूपड़ा साफ हो गया। बहुत शोरशराबे और मीडिया में विरुद के बावजूद कोयंबटूर में अन्नामलै विफल रहे और चेन्नै दक्षिण में राज्यपाल पद त्याग कर चुनाव मैदान में उतरी सुश्री सौन्दरराजन को 3 की पराजय का सामना करना पड़ा। द्रमुक नेता स्तालिन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने सभी 39 में सीटों पर जीत का परचम लहराया। यही नहीं, राज्य से सटे केन्द्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरि की इकलौती सीट पर कांग्रेस के निवर्तमान सांसद वी. वैथिलिंगम ने अपना कब्जा बरकरार रखा। औपनिवेशिक काल की खुमार में डुबे इस सुरम्य सूबे में इकलौती लोकसभा सीट जीतने का बीजेपी का बलूना संसूबा बंगाल की खाड़ी की लहरों में बह गया। पुदुच्चेरि से लगातार दूसरी बार निर्वाचित वी. वैथिलिंगम कांग्रेस के वरिष्ठ और सम्मानित नेता है। उनके जीवन- चरित के हरूफ चमकीले और चटख हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि काबिले फख है और पाग में कई कलंगिया । उनके पूर्वजों ने फ्रेंच शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके दादा रेडियर नेट्टापक्कम कम्यून के मेयर रहे और पिता ने सूबे की कमान संभाली। चेन्नै के लोयोला कालेज में पढ़कर वह गृहनगर मट्टुक्करै लोट आये और खेती करने लगे, लेकिन राजनीति उनको नियति थी। फलतः वह सन 1985 में पहले पहल एमएलए और सन 1990 में सीएम बने। उनके कार्यकाल में उद्योग और शिक्षा की खूब प्रगति हुई और इसी ने राजनीति में उनकी लंबी पारी की आधारशिला रखी। तो आठ बार एमएत्लए, एक बार सीएम, स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष रह चुके 73 वर्षीय वैथिलिंगम पुदुच्चेरि से दोबारा एमपी चुने गये हैं। वह पुदुच्चेरि कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। इस बार उन्होंने बीजेपी के नमस्सिवायम को कश्मकश भरे मुकाबले में हराया। एक छोटे से सूबे में कांग्रेस की यह जीत लोगों को साधारण भले ही लगे, लेकिन राजनीतिक निहितार्थों के मान से यह एक बड़ी जीत है और यह जीत द्रमुक और कांग्रेस के गठजोड़ को मजबूती प्रदान करती है। वी. वैथिलिंगम की इस जीत में द्रमुक का उल्लेखनीय योगदान रहा और तमिलनाडु के चतुर-सुजान मुख्यमंत्री स्तालिन के बेटे उदयनिधि ने पुदुच्चेरि में सघन प्रचार के साथ-साथ प्रभावशाली रोड-शो भी किया।

इसमें शक नहीं कि पुदुच्चेरि और तमिलनाडु में इकतरफा (और प्रभावशाली जीत से स्तालिन के नेतृत्व में द्रमुक का राजनीतिक बल और मनोबल बढ़ा है। इससे स्तालिन का 1 प्रभामंडल और चमकीला हुआ है। गठबंधन गठन के शिल्पी होने से सारा श्रेय उनके खाते में गया है। स्तालिन की नजर अब 2026 के विधानसभा चुनाव पर है। और वह इसी चिड़िया की आंख का निशाना साध रहे हैं। यह अकारण नहीं कि अन्नाद्रमुक की पूर्व अंतरिम महासचिव वीके शशिकला और जेसीडी प्रभाकर ने अन्नाद्रमुक विभिन्न धड़ों और गुटों के बीच एकता की अपील की है। पौ बारह है। कांग्रेस और वामदल उसके बगलगीर हैं। यह अपील कितना भी रंग क्यों न लाये, अभी तो द्रमुक की ड्ट स्तालिन के रिश्तों में बीते बरसों में खटास लगातार बढ़ी है। दोनों के दारम्यां ऐसी फसीलें उग आई है, जिनका लंबे समय तक ढहना आसान नहीं है। सन 2019 में उत्तरी राज्यों में संतृप्त बिंदू तक पहुंच चुकी बीजेपी को वहाँ क्षरण का अंदाजा था। इसी के चलते उसने दक्षिणी राज्यों से भरपाई की योजना तैयार की थी। पीएम मोदी ने डेक्कन - स्टेट्स के लगातार दौरे किये और दक्खिनी राज्यों में भारी राजनीतिक पूंजी झोंकी। लेकिन इस निवेश के नतीजे मोदी की मन माफिक नहीं निकले। डेक्कन की कुल जमा 131 सीटो में से सर्वाधिक 42 सीटों पर बाजी मारी कांग्रेस ने और तेज रफ्तार की अभ्यस्त बीजेपी उससे तेरह कदम पीछे 29 पर अटक गयी। आश्चर्यजनक तौर पर उसे तेलंगाना फला। पिछली बार चार के मुकाबले इस बार वह आठ पर जीती। आन्ध्र में चंद्रबाबू नायडू की बदौलत उसे तीन में विजय मिली। कर्नाटक का उसका दुर्ग तो नहीं ढहा, लेकिन गत बार की 25 के मुकाबले वह 17 सीटें ही जीत सकी।

तमिलनाडु में अंकतालिका में सिफर पर रहने का दुःख बीजेपी को अगले पाच साल सालता रहेगा। मोदी और शाह -3 की जोड़ी को तमिलनाडु से बड़ी उम्मीद थी और उन्होंने यहां कमल खिलाने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी थी। उन्हें अन्नामलै जैसा तुर्श नेता भी मिल गया, लेकिन द्रविड़ राजनीति के इस भूखंड में उसका सुर-ताल नहीं बदला, ड्ट लिहाजा अन्नाद्रमुक से उसका गठबंधन टूट गया। बीजेपी ने इस अलगाव का खामियाजा भुगता। तमिलनाडु में सन 2026 में विधान सभा के चुनाव होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि दो द्रविड़ पार्टियों की सैंडविच्ड- सियासत में बीजेपी कैसे सेंध लगाती है। अनुमान यही है कि बीजेपी के लिये तमिलनाडु में अंगूर खट्टे रहेंगे, क्योंकि अन्नाद्रमुक के महासचिव ई. के. पलनीस्वामी ने दो टूक कह दिया है कि उनकी पार्टी बीजेपी से कोई समझौता नहीं करेगी और चुनाव मैदान में अकेली उतरेगी।

केरल की राजनीति को भी गठबंधनों की राजनीति के लिये जाना जाता है। वहां की सियासत यूडीएफ और एलडीएफ में उलझी हुई है। बीजेपी वहाँ बरसों से किसी विधि पांव टिकाने की कोशिश कर रही है। अंततः इस बार केरल के सियासी बाग से पहला कमल खिला । त्रिचूर से उसके उम्मीदवार और लिने-कैलाकार नेता गोपी सुरेश विजयी हुए। सिनेमा से संसद में पहुंचे गोपी फिलवक्त अपने बयानों के कारण सुर्खियों में हैं। एक ओर तो उन्होंने पद के प्रति अनिच्छा व्यक्त की है, दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस- नेत्री (स्व.) श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति प्रशंसात्मक उद्गार व्यक्त किए हैं। उनका इंदिरा-अम्मा को 'मदर इंडिया' की संज्ञा देना बीजेपी नेतृत्व को नागवार गुजर सकता है।

नतीजों पर सरसरी नजर डालें तो दिलचस्प तस्वीर उभरती 1 है। कुल 20 में से 18 कग्रिसनीत यूडीएफ के खाते में और एक-एक सीट क्रमशः माकपानीत एलडीएफ और बीजेपीनीत एनडीए के हक में वाम मोर्च के इकलौते विजयी उम्मीदवार रहे के. राधाकृष्णन। उन्होंने अलाथुर की ई सीट कांग्रेस से छीनी। इसे एकबारगी छोड़ दे तो वाम- शिविर की एमी राजा के अलावा केके शैलजा, टीएम थामस, इसाक, ई० करीम, ए० विजयराघवन, एमबी जयराजन और पी. रवीन्द्रन चुनाव हार गये। कांग्रेस की इकतरफा लहर में भगवा-शिविर के मल्लों के भी पाँव उखड़े। राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस के बहुचर्चित प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद शशि थरूर पर बढ़त बना ली थी, लेकिन अंततः थरूर 16077 वोटों से विजयी रहे। शिविर की बात करें तो वी. मुरलीधरन, के० सुरेन्द्रन, एमटी रमेश, शोभा सुरेन्द्रन और अनिल एंटोनी को पराजय का सामना करना पड़ा। बीजेपी की सहयोगी भारत धर्म जन सेना के, तुषार वेलापल्ली चुनावी दौड़ में कोट्टायम में तीसरे स्थान पर रहे।

केरल में कांग्रेस का प्रदर्शन वाकई शानदार रहा। वायनाड से राहुल गांधी का जीतना तय था, लेकिन केरल में सर्वाधिक तीन लाख 64 हजार से अधिक वोटों की जीत से उनका सियासी कद ऊंचा हुआ। कांग्रेस का विजय- रथ पूरे प्रदेश में घूमा। कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को बखूबी छकाते हुये कासरगोद, कन्नूर, वडकरा, कोझीकोड, वायनाड, तिरुवनंतपुरम, पलक्कड़, चलकुड़ी, एनाकुलम, एटिंगल, इडुक्की, मावेलिवकरा, पथनमथिट्टा और अलप्पुझा में जीत का परचम लहराया। उसके सहयोगी दलो में आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर और अब्दुस्समद समदानी ने क्रमशः मलप्पुरम और पोन्नानी की सीटें जीती। ऐसे ही आरएसपी के प्रेमचंद्रन कोल्लम से जीते। इस दास्ताने-सियासत का क्षेपक यह है कि राहुल के इस्तीफे के बाद अब प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। दूसरी बात यह कि शशि थरूर का यह अंतिम चुनाव था। अगली बार त्रिवेंद्रम में कोई नया प्रत्याशी नमूदार होगा। इस रंग बदलती राजनीति में दक्षिण की दिशा यकीनन काबिलेगौर है।

65प्रशित आरक्षण पर पटना उच्च न्यायालय का नीतिश सरकार को झटका

इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय पीठ ने कहा था कि आरक्षित स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए।

गौरव कुमार व अन्य के द्वारा दायर याचिका में हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के बाद फैसला 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया था। जो अब सुनाया गया है। राज्य सरकार का तर्क था कि उसने यह आरक्षण आनुपातिक आधार पर नहीं, इन वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण दिया था। नीतीश सरकार ने 9 नवंबर, 2023 को इस सम्बन्ध विधानसभा से कानून पास किया था। नीतीश सरकार ने इसके बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से 65 फीसदी कर दिया था।

समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। यही कारण है कि आजादी के पहले जो जातीय जनगणना हुई थी उसके बाद देश में कोई जातीय जनगणना नहीं हुई जिससे यह जाना जा सके कि वास्तव में आबादी का क्या प्रतिनिधित्व है। सांविधानिक स्थिति के अनुरूप सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर क्या स्थिति है। आरक्षण का उद्देश्य उन लोगों को मुख्यधारा में लाना था जो किन्हीं कारणों से समाज में सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े रह गए थे। यही कारण है कि ओबीसी के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को भी शामिल किया है जिससे जो आगे बढ़ चुके हैं उनके बजाय जो पीछे रह गए हैं उन्हें उसका लाभ मिल सके। दक्षिण भारत के कई राज्यों में आरक्षण पचास फीसदी से अधिक है। कुल मिलाकर देखा जाये तो देश में जो स्थिति पैदा हो गयी है उससे यह जरूरी हो गया है कि नये सिरे से जातीय जनगणना हो और सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के बारे में नई सूची तैयार हो जिससे जो पीछे रह गए हैं उन्हें भी मुख्यधारा में लाया जा सके।

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के 65 फीसदी आरक्षण को रद्द कर दिया है जिसे नीतीश सरकार ने राज्य में सर्वे कराकर लागू किया था इसमें अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति ड्ट और जनजाति शामिल है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय किया है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार के दौरान बिहार में जातीय जनगणना के नाम पर किए गए सर्वे के आधार पर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल आरक्षण सीमा पचास फीसदी से बढ़ाकर सर्वे में किए गए आंकड़ों के आधार पर राज्य में 65 फीसदी कर दी थी। एक ओर जहां विपक्षी दल जातीय जनगणना की मांग को लेकर आगे बढ़ रहे थे वहीं, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी। अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण भारतीय जनता पार्टी न तो आरक्षण के बारे में कुछ ज्यादा बोल पाती है और न ही जातीय जनगणना के बारे में ही वह खुला समर्थन कर पाती है। चुनाव के दौरान जरूर इस तरह की बातें होती हैं कि हम आरक्षण को खत्म करने के पक्ष में नहीं हैं। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार द्वारा किए गए 65 फीसदी आरक्षण को रद्द करते हुए एक झटका जरूर दे दिया है। यह बात. दूसरी है कि जो नीतीश कुमार राजद के साथ सरकार चला रहे थे वहीं अब भाजपा के साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं। यही नहीं अब वह राजग के भी घटक हैं और केन्द्र सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी है ।उत्तर प्रदेश में भी राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्रित्वकाल में पिछड़ा, अतिपिछड़ा को अलग तरह से परिभाषित किया गया था लेकिन राज्य सरकार के इस श्रेणी विभाजन को अदालत ने नहीं माना था। संविधान में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा गया है। यही कारण है कि सामाजिक और शैक्षिक पिछडेपन की खोज के लिए 1950 में काका कालेलकर और 1978 में बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। बी पी मंडल की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के दौरान लागू किया गया था जिसके अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिया गया। चूंकि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन की आधार जातियां ही हैं इसलिए आरक्षण भी जाति के आधार पर मिलता है जो पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल हैं। संविधान में संशोधन करके मोदी सरकार द्वारा दस फीसदी आर्थिक आधार पर गरीबी की रेखा का आरक्षण भी दे दिया गया है। केन्द्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के सम्बन्ध में रोहिणी आयोग का गठन 2017 में किया था। इसका उद्देश्य

उन जातियों को देखना था जो ओबीसी आरक्षण की सूची में हैं लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। जहां तक आरक्षण दिये जाने का सम्बन्ध है। आरक्षण के मामले में इंदिरा साहनी का मामला हमेशा नजीर के रूप में पेश होता आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुल आरक्षण पचास फीसदी तक सीमित कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने जब मराठा आरक्षण लागू किया था तब सुप्रीम कोर्ट ने साफतौर पर कहा था कि इंदिरा साहनी के मामले में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। हम इसे बड़ी बेंच को नहीं भेज सकते। **गौरव कुमार व अन्य के द्वारा दायर याचिका में हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के बाद फैसला 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया था। जो अब सुनाया गया है। राज्य सरकार का तर्क था कि उसने यह आरक्षण आनुपातिक आधार पर नहीं, इन वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण दिया था। नीतीश सरकार ने 9 नवंबर, 2023 को इस सम्बन्ध विधानसभा से कानून पास किया था। नीतीश सरकार ने इसके बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से 65 फीसदी कर दिया था।**

आखिर क्यों चुप्पी साध गई पक्षियों की चहचाहट ?

पक्षियों को पर्यावरण की स्थिति के सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक माना जाता है। क्योंकि वे आवास परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं और पक्षी पारिस्थितिकीविद् के पसंदीदा उपकरण हैं। पक्षियों की आबादी में परिवर्तन अक्सर पर्यावरणीय समस्याओं का पहला संकेत होता है। चाहे कृषि उत्पादन, वन्य जीवन, पानी या पर्यटन के लिए पारिस्थितिक तंत्र का प्रबंधन किया जाए, सफलता को पक्षियों के स्वास्थ्य से मापा जा सकता है। पक्षियों की संख्या में गिरावट हमें बताती है कि हम आवास विखंडन और विनाश, प्रदूषण और कीटनाशकों, प्रचलित प्रजातियों और कई अन्य प्रभावों के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

बदल रहे हर रोज ही, हैं मौसम के रूप ।
सर्दी के मौसम हुई, गर्मी जैसी धूप ।।
सूनी बगिया देखकर, ह्यतितली है खामोशह्ल ।
जुगनूं की बारात से, गायब है अब जोश ।।

हाल ही की एक रिपोर्ट, 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स' के अनुसार, दुनिया भर में मौजूदा पक्षी प्रजातियों में से लगभग 48% आबादी में गिरावट के दौर से गुजर रही है या होने का संदेह है। प्राकृतिक प्रणालियों के महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में पक्षियों का पारिस्थितिक महत्व है। पक्षी कीट और कृंतक नियंत्रण, पौधे परागण और बीज फैलाव प्रदान करते हैं जिसके परिणामस्वरूप लोगों को ठोस लाभ होता है। कीट का प्रकोप सालाना करोड़ों डॉलर के कृषि और वन उत्पादों को नष्ट कर सकता है। पर्पल मार्टिंस लंबे समय से हानिकारक कीटनाशकों के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लागत (आर्थिक लागत का उल्लेख नहीं) के बिना कीट कीटों की आबादी को काफी हद तक कम करने के एक प्रभावी साधन के रूप में जाना जाता है।

आती है अब है कहाँ, कोयल की आवाज ।
बूढा पीपल सूखकर, ठूंठ खड़ा है आज ।।
जब से की बाजार ने, हरियाली से प्रीत ।

देश में नशे के फैलते जालका सबसे चिंताजनक पक्ष

दुनिया भर में 26 जून को नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। यह दिवस समाज के हर वर्ग के लिए आत्मचिंतन का विषय है, क्योंकि मादक पदार्थों का सेवन अब मानवता के प्रति सबसे बड़े अपराध का रूप धारण कर चुका है। भारत में मादक पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। चिंता का विषय यह है कि अब यह प्रवृत्ति केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी नशे का जाल फैलता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में अफीम, चरस, गांजा, हेरोइन आदि के अलावा इंजेक्शन के जरिये लिए जाने वाले मादक पदार्थों का भी इस्तेमाल होने लगा है। रईसजादे युवक-युवतियों की रेव पार्टियां तो नशे का भयावह आधुनिक रूप है, जहां राजनीतिक संरक्षण के चलते प्रायः पुलिस भी हाथ डालने से बचती है। हालांकि कभी-कभार रेव पार्टियों पर छापा मारकर नशे में मदहोश युवाओं को गिरफ्तार किया जाता है। देश का कोई भी महानगर ऐसा नहीं है, जहां ऐसी रेव पार्टियां रईसजादों की रोजमर्रा की जीवनशैली का हिस्सा न हों। वास्तव में रेव पार्टियां बिगड़ैल युवाओं की नशे की पार्टियों का ही आधुनिक रूप हैं। कोकीन हो या अन्य ऐसे ही मादक पदार्थ, जिनमें गंध नहीं आती, रसूखदार परिवारों के बिगड़े हुए युवाओं का मनपसंद नशा बनते जा रहे हैं। इस बात से बेखबर कि ये तमाम मादक पदार्थ सीधे शरीर के तंत्रिका तंत्र पर हमला करते हैं और शरीर को भयानक बीमारियों की सौगात देते हैं, ऐसे युवा चंद पलों के मजे के लिए इनके गुलाम बन जाते हैं। युवाओं को मादक पदार्थों के करीब लाने में इंटरनेट की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों में करीब चालीस फीसदी कॉलेज छात्र हैं, जिनमें लड़कियों की संख्या भी काफी ज्यादा है। देश के अनेक कॉलेजों में तो अब स्थिति यह है कि आसानी से नशीले पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। स्कूल-कॉलेजों के छात्र अक्सर अपने साथियों के कहने या दबाव डालने पर या फिर मॉडर्न दिखने की चाहत में इनका सेवन आरंभ करते हैं। कुछ युवक मादक पदार्थों से होने वाली अनुभूति को अनुभव करने के लिए, कुछ रोमांचक अनुभवों के लिए तो कुछ मानसिक तौर पर परेशानी अथवा हताशा की स्थिति में इनका सेवन शुरू करते हैं। मानव जीवन की रक्षा के लिए बनाई जाने वाली कुछ दवाओं का उपयोग भी लोग अब नशा करने के लिए करने लगे हैं।

देश में नशे के फैलते जाल का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि मादक पदार्थ न सिर्फ मानव शरीर की सुंदरता को नष्ट कर शरीर को खोखला बनाते हैं बल्कि इनका उपयोग युवा पीढ़ी की क्षमताओं को नष्ट कर उनकी सृजनशीलता को भी मिटा रहा है तथा देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को पंगु बना रहा है। एक बार मादक पदार्थों की लत लग जाए तो व्यक्ति इनके बिना रह नहीं पाता। यही नहीं, उसे पहले जैसा नशे का प्रभाव पैदा करने के लिए और अधिक मात्रा में मादक पदार्थ लेने पड़ते हैं। इस तरह व्यक्ति इनका गुलाम बनकर रह जाता है। अधिकांश लोगों में गलत धारणाएं विद्यमान हैं कि मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति की सृजनशीलता बढ़ती है और इससे व्यक्ति में सोच-विचार की क्षमता, एकाग्रता तथा यौन सुख बढ़ता है लेकिन वास्तविकता यही है कि नशे के शिकार लोगों की सोच-विचार की क्षमता और इसकी स्पष्टता खत्म हो जाती है तथा उनके कार्यों में भी कोई तालमेल नहीं रहता। इनके सेवन से कुछ समय के लिए संकोच की भावना जरूर मिट जाती है लेकिन अंततः इससे शरीर की सामान्य कार्यक्षमता में गिरावट आती है। दरअसल नशीली दवाएं या नशीले पदार्थ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर की कार्यप्रणाली को बदल देते हैं। वर्ष 1993 में प्रकाशित पुस्तक ह्यमौत को खुला निमंत्रणह्न में बताया गया है कि कोई भी रसायन, जो किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक कार्यप्रणाली में बदलाव लाए, मादक पदार्थ कहलाता है और जब इन मादक पदार्थों का उपयोग किसी बीमारी के इलाज या बेहतर स्वास्थ्य के लिए दवा के तौर पर किया जाए तो यह मादक पदार्थों का सही उपयोग कहलाता है लेकिन जब इनका उपयोग दवा के रूप में न होकर इस प्रकार किया जाए कि इनसे व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचे तो इसे नशीली दवाओं का दुरूपयोग कहा जाता है। मादक पदार्थों के सेवन का आदी हो जाने पर व्यक्ति में प्रायः कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, जिनमें खेलकूद और रोजमर्रा के कार्यों में दिलचस्पी न रहना, भूख कम लगना, वजन कम हो जाना, शरीर में कंपकंपी छूटना, आंखें लाल, सूजी हुई रहना, दिखाई कम देना, चक्कर आना, उल्टी आना, अत्यधिक पसीना आना, शरीर में दर्द, नींद न आना, चिड़चिड़ापन, सुस्ती, आलस्य, निराशा, गहरी चिन्ता इत्यादि प्रमुख हैं। सूई के जरिये मादक पदार्थ लेने वालों को एड्स का खतरा भी रहता है।

देशभर में नशे का अवैध व्यापार तेजी से फल-फूलने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि नशे के सौदागरों के लिए मादक पदार्थों की तस्करी सोने का अंडे देने वाली मुर्गी साबित हो रही है। विश्व की कुल अर्थव्यवस्था का 15 फीसदी हिस्सा यही व्यापार रखता है। भारत में मादक पदार्थों की तस्करी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, बर्मा, ईरान आदि देशों के जरिये होती रही है और अवसर मिलते ही ये मादक पदार्थ तस्करी के जरिये पश्चिमी देशों में पहुंचा दिए जाते हैं। हालांकि भारत इस अवैध व्यापार में तस्करों के लिए केवल एक पड़ाव का काम करता है लेकिन इसके दुष्प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि इस अवैध व्यापार का तस्करी, आतंकवाद, शहरी क्षेत्र के संगठित अपराध तथा आर्थिक एवं व्यावसायिक अपराधों से काफी करीबी रिश्ता है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भौगोलिक स्थिति के कारण भारत नशीली दवाओं की तस्करी के लिए सबसे अच्छा रास्ता बन गया है।

हालांकि नशे के अवैध व्यापार पर लगाम कसने के लिए हमारे यहां अन्य देशों के मुकाबले बहुत कड़े कानून हैं, फिर भी अपराधी अक्सर कानून की कुछ खामियों की वजह से बच निकलते हैं। यही कारण है कि मादक पदार्थों का अवैध व्यापार भारत में निरंतर फल-फूल रहा है। आज युवा पीढ़ी जिस कदर मादक पदार्थों की शिकंजे में फंस रही है, उसके मद्देनजर समाज का कर्तव्य है कि वह युवा वर्ग का मार्गदर्शन करते हुए उसे उचित मार्ग दिखलाए और गलत मार्ग पर चलने से रोके। ऐसे कार्यों को केवल सरकार के ही भरोसे छोड़ देना उचित नहीं बल्कि समाज को भी इस दिशा में ठोस पहल करनी होगी।

युवाओं, महिलाओं को अवसर प्रदान करने में दीदी सबसे आगे

भले ही पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टी के शासन की समाप्ति 2011 में हो गयी थी, लेकिन दीदी की कार्यशैली में उसकी संस्कृति आज भी दिखाई देती है। बंगाल में गरीब से गरीब व्यक्ति भी सम्मानपूर्वक जी सकता है अमीर से अमीर और गरीब से गरीब दो अलग-अलग क्लास को अपनी आजीविका के अनुसार जीवनयापन करते हुए आप यहां देख सकते हैं

पश्चिम बंगाल जिसके उत्तर में नेपाल, भूटान और सिक्किम है पूर्व में असम, बांग्लादेश है। पश्चिम में बिहार और झारखंड है तथा दक्षिण में ओडिशा और झारखंड दोनों हैं। पश्चिम के दक्षिण में गंगा का मैदान और उत्तर में हिमाचल क्षेत्र है जो दो मुख्य प्राकृतिक क्षेत्र कहे जाते हैं। ईसापूर्व तीसरी सदी में बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र अशोक साम्राज्य का हिस्सा था। चौथी सदी में यह गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बन गया। पश्चिम बंगाल में 13वीं शदी से लेकर 18वीं शताब्दी तक कई सुल्तानों और जमींदारों का शासन रहा। 1857 की प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपना वर्चस्व यहां पर कायम किया। बंगाल को भारतीय संस्कृति नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। साहित्य, कला और समाज-सुधर की शुरुआत बंगाल से ही हुई है भारत के स्वाधीनता संग्राम का मुख्य केन्द्र भी बंगाल रहा है और इसी के साथ भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियों का एक महत्वपूर्ण उद्गमस्थल भी रहा है। एक ओर यह उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का गढ़ था तो दूसरी ओर रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने राष्ट्रवाद की आलोचना भी बंगाल की भूमि पर ही की थी। औपनिवेशिक काल में 1905 में साम्प्रदायिक आधार पर बंगाल विभाजन किया था। बंग-भंग के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त आंदोलन किया था परिणामस्वरूप1911 में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया। पश्चिमी संदर्भ में कम्युनलिज्म का अर्थ समुदाय आधारित कार्यवाही है। लेकिन जैसे ही भारतीय और दक्षिण एशियाई संदर्भ में इसका अनुवाद साम्प्रदायिकता या फिरकापरस्ती के रूप में किया जाता है, जिससे सामुदायिकता में निहित सकारात्मकता समाप्त हो पूरी तरह से नकरात्मकता में तब्दील हो जाती है। साम्प्रदायिकता का मतलब हो जाता है समुदायों के मध्य आमतौर पर धार्मिकके बीच, प्रतिस्पर्धा और टकराव जो अक्सर हिंसा का रूप लेती रहती है।

साम्प्रदायिकता की सामान्य और प्रचलित समझ यह हे कि इसका जन्म अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई 'फूट डालों और शासन करो' की कुटिल नीति के कारण हुआ था। 1857 के विद्रोह से पूर्व देश में कम से कम नौ-दस स्थानों पर हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। लेकिन विद्रोह के दौरान तीन वर्षों में हिन्दुओं और मुसलमानों ने जबरदस्त एकता का प्रदर्शन करके उपनिवेशवाद को हिला दिया था। विकासशील समाज अध्ययन पीठ के द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से यह बात सामने आई है कि 1990 के दशक में जब भारत के अधिकांश राज्यों में राजनीति के केन्द्र में मंदिर और मंडल कमीशन हावी था वहीं इस दौर में ऊंची-जातियों, पिछड़ी जातियों, हिन्दू और मुसलमानों ने जाति धर्म से परे बंगाल में वाम-मोर्चे का समर्थन किया। 1984 और 1992 के साम्प्रदायिक दंगों के बाद भी पश्चिम बंगाल साम्प्रदायिक सद्भाव और सेकुलर मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो कभी भारत की राजधानी भी रही है और जिसे हम 'सिटी ऑफ जॉयके नाम से जानते हैं।

कोलकाता की रूमानियत कहें या जादू हमारे अवचेतन मन में कहीं न कहीं हमेशा मौजूद रहा है, चाहे वह संगीत, लोकगीतों, उपन्यासों, कहानियों, फिल्मों या अन्य किसी विधा के माध्यम से हो। पश्चिम बंगाल में भारतीय राजनीति में पारंपरिक तरीके को नए यप में प्रस्तुत करने का और नए रूपकों के गढ़ने की प्रक्रिया 2011 के बाद से शुरू होती है, जब 34 साल के लंबे या कहें एकतरफा कम्युनिस्ट शासन को चुनौती देने का काम ममता बनर्जी के द्वारा किया जाता है और जिसमें वह जीत हासिल करती हैं, इसमें एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि वे कम्युनिस्ट पार्टी को जरूर चुनौती देती हैं लेकिन उनके मूल्यों का समावेश अपनी जीवनशैली और पार्टी की विचारधारा में भी करती हैं। राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत के तौरपर ममता बनर्जी की जीत को देखा जा सकता है। जो भारतीय राजनीति में पावन वूमेन का इतिहास रचती हैं और नए एक अध्याय की शुरुआत कती प्रतीत हो रही हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद के तीसरे टर्म को पूरा करेंगी। बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने तक का सफर लंबा और संघर्षपूर्ण था। आसान नहीं खासकर आज के समय में जब राजनीति से नैतिकता का लगातार लोप हो रहा हो। इसके पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी को यह दर्जा हासिल था। दीदी का तीसरा टर्म उन सभी महिलाओं की जीत है जो अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं ओर राजनीति में भी अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए आतुर हैं साथ ही अपनी उपस्थिति से समाज में फैल रहे जहर को समाप्त करना चाहती हैं इसके साथ ही उन लोगों की छोटी सोच को भी जो महिलाओं को दोयम दर्जे का समझती हैं और वह स्त्री देह से परे कुछ देखने-समझने लायक भी नहीं हैं। इसमें दीदी का बखूबी साथ निभया है वहां की महिला मतदाताओं ने, जो पितृसत्ता की घिसी-पिटी परिपाटी के बंधनों को तोड़कर अवधारणाओं को खंडित करते हुए एक नई राजनीतिक चेतना का संचार करने में लगी हुई हैं। साथ ही साथ वह यह संदेश भी दे रही हैं कि आधी आबादी की उपेक्षा कर सत्ता पर काबिज नहीं हुआ जा सकता है।

वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण रहा जिस पर हर व्यक्ति की आंख लगी थी जो आज भी बदलाव का इंतजार कर रहा है और राष्ट के सेकगुलर स्वरूप को तथा देश को संविधान और लोकतांि9क मूल्यों से संचालित रखने में विश्वास करते हैं। इसी के साथ विकास को लेकर चिंतित और परेशान भी हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का विकास ही नहीं सभी की शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार, अिाव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा भी निहित हो साथ ही धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा के आधार पर विभाजित करने वाले लोगों के खिलाफ जो सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं इनकी राजनीति लोगों को विभाजित करने वाले लोगों केखिलाफ भी जो सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा केचलते एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हें, इनकी राजनीति लोगों को विभाजित करने से ही सफल होती है। अराजकता का माहौल जो लगातार बनाया जा रहा था, इस बार वह जरूर टूटा, होगा और यह बात भी समझ आई होगी कि सिर्फ विभाजित कर लोगों को नहीं जीता जा सकता है, विशेषकर बंगाल को नहीं ही। जो लोग तथाकथित विकास के दम पर सत्ता में काबिज हुए थे वह विकास भी कुछ लोगों का ही कर रहे थे, जबकि वे सबके विकास की बात करते थे यह भ्रम भी इस चुनाव में समाप्त हुआ है। इस लोकसभा चुनाव में और 2014 के बाद से राजनीति में जो एक दूसरे का सम्मान होता था चाहे वहप्रतिपक्षी ही क्यों न हो ध्वस्त हुआ है। व्यक्तिगत जीवन को भी सार्वजनिक मंच पर लाकर छोटा बनाने का काम अब राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा न होते हुए भी ममता बनर्जी ने एक नई प्राण उऊर्जा का संचार विपक्ष में अपने बेबाक अंदाज में किया, जिसें लोग कायल हैं। बंगाल को जिस तरह से महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया है हम उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी पूरे भारत को सुरक्षित बनाने और महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया है हम उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्ज्री पूरे भारत को सुरक्षित बनाने और महिलाओं के राजनीति में प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल से 12 महिला प्रतिनिधि संसद में पहुंची हैं जो लगातार प्रतिरोध की बंगाल संस्कृति को कायम रखेंगी।

महुआ मोइत्रा से हम सभी वाकिफ हैं यही उम्मीद हम अन्य महिला प्रतिनिधियों से भी कर सकते हैं। रणधीर सिंह के अनुसार, समकालीन भारत में अपनी विचारधारा और व्यवहार के रूप में साम्प्रदायिकता शासक वर्गों द्वारा की जाने वाली राजनीति का एक प्रचार है। उनकी यह स्वीकारोक्ति है कि साम्प्रदायिक राजनीतिक खेल एक ऐसे समाज में खेला जाता है जो अपनी सामंती-औपनिवेशिक विरासत की जकड़ में बुरी तरह से फंसा हुआ है, जो गहरे धार्मिक विभान का शिकार है और जो पूंजीवादी विकास के अपने एक विशिष्ट रूप से गुजर रहा हे। बंगाल को लेकर सेकलर बनाए रखने और साम्प्रदायिक ताकतों को रोकने का कार्य दीदी ने किया है और इसमें उनका साथ यहां की जनता ने दिया है ठीक उसी तरह जिस तरह से बंग-भंग के विभाजन को एक जुट होकर रोका गया था। बंगाल में हर जगह महिलाओं की अधिक संख्या में उपस्थिति किसी अन्य प्रदेश की महिलाओं को भी सुरक्षा का बोध कराती है। वर्ष 2012 में टाइम पत्रिका ने ममता बनर्जी को विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक का बताया था, इसके साथ ही ब्लूमबर्ग मार्केट पत्रिका ने भी उन्हें वित्त की दुनिया में 50 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया था। वर्ष 2013 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन द्वारा ममता बनर्जी को सबसे ईमानदार राजनेता के रूप में चुना गया था। महिलाओं, बच्चों और गरीबों की लड़ाई में दीदी ने हमेशा उनका साथ दिया है। दीदी ने हवालात में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों और उससे होने वाली मृत्यु के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। मानवाधिकारों को लागू करवाने के लिए भी लंबा संघर्ष उनके द्वारा किया गया है। भले ही पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टी के शासन की समाप्ति 2011 में हो गयी थी, लेकिन दीदी की कार्यशैली में उसकी संस्कृति आज भी दिखाई देती है।

बंगाल में गरीब से गरीब व्यक्ति भी सम्मानपूर्वक जी सकता है अमीर से अमीर और गरीब से गरीब दो अलग-अलग क्लास को अपनी आजीविका के अनुसार जीवनयापन करते हुए आप यहां देख सकते हैं रूस में आयोजित 'वर्ल्ड वुमन राउंड टेबल कांफ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व भी दीदी के द्वारा किया गया है।

दीदी ने महिला अस्मिता के प्रश्नों को प्रमुखता से उठाया है और उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने का प्रयास भी लगातार कर रही हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में भी तृणमूल कांग्रेस की दो सबसे कम उम्र की सांसादों को संसद तक पहुंचाने में दीदी की ही महत्वपूर्ण भूमिका है जो उन पर विश्वास और जिम्मेदारी को बढ़ाता है। पार्टी में युवाओं, महिलाओं को अवसर प्रदान करने में दीदी सबसे आगे हैं।
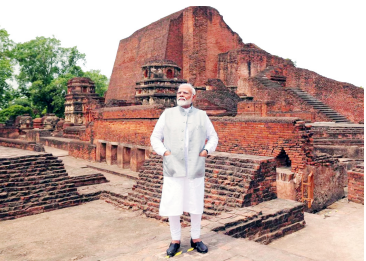
भारत में विश्वविद्यालयों की मौजूदा स्थिति विचारणीय

दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव ऐसा था जिसने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया। नालंदा में चिकित्सा, आयुर्वेद बौद्ध धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान, और भारतीय दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। भारतीय गणित के प्रणेता और शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट छठी शताब्दी ईसवी के दौरान नालंदा के प्रतिष्ठित शिक्षकों में से एक रहे।

इतिहासकारों के अनुसार, सदियों पहले नालंदा में दाखिला आसान नहीं था, यहां प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को कठिन साक्षात्कार प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह सब इतना वैभवशाली था, जो आसुरी शक्तियों और विध्वंसक विचारधारा के पोषकों को फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। आसुरी शक्तियों ने समय-समय पर हमारे वैभव को मिटा कर हमें निराश और हताश और आहत करने के लिए प्रयास किए। अतीत में समय चक्र कुछ ऐसे चला जिससे आसुरी शक्तियों हावी हो गईं। विदेशी आक्रांताओं की वजह से एक लंबे कालखंड तक देश में प्रतिकूल हालात बने रहे। आक्रांताओं ने हमारे नालंदा जैसे विशाल भवन नष्ट कर दिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। इसी के साथ सदियों के बाद नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ज्ञान के प्रसार के लिए उठ खड़ा हुआ है। चार सौ पचपन एकड़ में 1749 करोड़ की लागत से बना नालंदा का नया परिसर केवल कंकरीट की एक इमारत भर नहीं है, बल्कि इस इमारत के निर्माण से हमारे देश का गौरवशाली इतिहास पुनर्जीवित हुआ है। यह भारत को विश्व गुरू बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ा एक महत्वपूर्ण कदम है जिसके जरिए समूची दुनिया में ज्ञान की अलख जगाने के साथ-साथ एक नया इतिहास रचा जाना तय हो गया है।

सदियों पहले समूचे विश्व के लिए ज्ञान का सागर बने जिस नालंदा को आक्रांताओं ने जला कर खाक और तहस-नहस कर दिया था, उसका पुनरुत्थान एक बहुत बड़ा और युगांतकारी कदम है। नालंदा में प्राचीन विश्वविद्यालयके खंडहरों के पास नई इमारत की तामीर हमें गौरवान्वित कर रही है। वैसे तो इमारतें रोज बनती हैं, मगर नालंदा में यह नवनिर्माण अनूठा है, देश के लिए गर्व का विषय है। नालंदा में मोदी ने कहा भी है कि मैं नालंदा को भारत की विकास यात्रा के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा मंत्र है गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तक भले ही जल जाएं लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकतीं। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। इब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रही है। नालंदा में लगाई गई आग किसी इमारत, पुस्तकालय को नष्ट करने का नहीं बल्कि भारत के गौरव को आहत करने का प्रयास था क्योंकि प्राचीन मगध सम्राज्य (आधुनिक बिहार) में स्थापित 5 वीं शताब्दी ई. में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय का नाम समूची दुनिया में था। इसमें दुनिया भर के दस हजार विद्यार्थी पढ़ते थे।

हमारे अस्तित्व के खात्मे की कोशिशें की गईं मगर वह ज्ञान को भला किस प्रकार मिटा पाते। उस ज्ञान को कैसे मिटाते, जो हमारे सहज स्वभाव में है। वक्तीतौर पर भवनों को ढहा देने वाले आक्रांता खुश होकर चले गए, लेकिन जिस प्रकार काले बादलों का अंधेरा छंटने पर सूर्य की सप्त रश्मियां वातावरण को फिर से जगमग कर देती हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और उत्कृष्टता के रूप में नामित नालंदा विश्वविद्यालय से पुनः शिक्षा का उजियारा फूटना शुरू हो गया है। अन्य शब्दों में स्पष्टतया कह सकते हैं किशिक्षा और विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा की सीढ़ी चढ़कर ही विकास की प्रत्येक मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। यदि हम आजादी के सौ साल पूरे होने के अवसर पर वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं तो यह शिक्षा की बदौलत ही संभव है लेकिन यह इतना सरल और सहज नहीं है। इसके लिए देश के विश्वविद्यालयों के लिए जमकर काम करना होगा। सरकारी विश्वविद्यालयों को ऊर्जावान बनाना होगा। सभी राज्यों को अपने-अपने विश्वविद्यालयों का ढांचा मजबूत करने के लिए होड़ लगानी पड़ेगी। अभी देश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक शिक्षा और सरकारी विश्वविद्यालयों की जो हालत है, वह बेहद चिंताजनक है, आजादी के बाद सत्तर वर्षों में शिक्षा को नजरअंदाज ही किया गया है। बजट में शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए। इसी कारण हमारे सरकारी विश्वविद्यालय और अन्य उच्चतर संस्थान पिछड़ गए। हमारे देश में निजी विश्वविद्यालय निरंतर विस्तार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत यूजीसी की फंडिंग वाले विश्वविद्यालय पिछड़ रहे हैं।

हमारे ज्यादातर विश्वविद्यालयों का बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं है। उनमें विश्वस्तरीय स्मार्ट क्लासरूम का अभाव है। अच्छे ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, एकेडमिक ब्लॉक्स, और बेहतरीन लैब्स की कमी खलती है, जो भारत प्राचीन काल में समूचे विश्व में शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था, जिस भारत में उच्च शिक्षा के दुनिया के पहले विश्वविद्यालयों में शामिल सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उस भारत में विश्वविद्यालयों की मौजूदा स्थिति विचारणीय है। इस वजह से देश में उच्च शिक्षा गुणवत्ता के लिहाज से पिछड़ रहे हैं। धनवान लोगों के बच्चे तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले जाते हैं और कहीं करियर बनाकर बस भी जाते हैं। आम लोगों के बच्चे निजी विश्वविद्यालयों में शोषण झेल रहे हैं।

यूजीसी फंडिंग वाले विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारी जाए तो हालात बदले जा सकते हैं। ऐसा तभी संभव है जब हम हमारे विश्वविद्यालयों को विश्व रैंकिंग में लाएंगे। उन्हें बड़ा ब्रांड बनाने की दिशा में काम करेंगे।

हमारे ज्यादातर विश्वविद्यालयों का बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं है। उनमें विश्वस्तरीय स्मार्ट क्लासरूम का अभाव है। अच्छे ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, एकेडमिक ब्लॉक्स, और बेहतरीन लैब्स की कमी खलती है, जो भारत प्राचीन काल में समूचे विश्व में शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था, जिस भारत में उच्च शिक्षा के दुनिया के पहले विश्वविद्यालयों में शामिल सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उस भारत में विश्वविद्यालयों की मौजूदा स्थिति विचारणीय है।

हीट स्ट्राइक करने पर आमादा सूर्यदेव

आप सूरज को देवता मानिए या केवल एक ग्रह,लेकिन उसके कोप से बचने के लिए अपने आपको तैयार रखिये। सूरज यानी सूरजमल आजकल केवल भारत में ही नहीं वरने पुरी दुनिया में 'एयर स्ट्राइक' करने पर आमादा हैं और इस एयर स्ट्राइक की चपेट में आ रहे हैं वे तमाम लोग जो न अपने लिए ऐसी खरीद सकते हैं न कुलर। देश की एक बड़ी आबादी के पास पंखा तक खरीदने की हैसियत नहीं है। देश-दुनिया के हर कोने से सूरजमल के प्रकोप की खौफनाक खबरें आ रहीं हैं, लेकिन हम हैं कि जागने के लिए तैयार नहीं है।

धरती से 14.96 लाख किलो मीटर दर स्थित सूर्य पहली बार नहीं तप रहा। वो तो हमेशा से आग उगलता है लेकिन धरती पर रहने वाले हम लोग सुरजमल के ताप से अपने आपको बचा लेते थे, क्योंकि हमारे पास घने जंगल थे। सूरजमल की तप्त किरणे इन जंगलों में सीना तानकर खड़े विशालकाय वृक्षों की सघन छाया के सामने हथियार डाल देती थीं, लेकिन अब हमारे पास सूरजमल के कोप से बचने का प्राकृतिक छाता नहीं रहा। यदि है भी तो बेहद बुरी दशा में जीर्ण -शीर्ण, जो हमें न आग उगलती सूरज की किरणों से बचा सकता है और न इंद्र के प्रकोप से।.

हम लोग राजनीति के बारे में जानते हैं, धर्म के बारे में जानते हैं। लेकिन सूरजमल के बारे में नहीं जानते। हम में से बहुत से लोग सूरजमल को सुबह-सवेरे उठकर जल अर्पित करते हैं ताकि उसकी आत्मा तृप्त रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। भारत में तो अनेक सूर्य मंदिर हैं जिनमें नित्य सूर्य को पूजा जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है, लेकिन सूरजमल दिनों-दिन आक्रामक्र हो रहे हैं। वे न धर्म देख रहे हैं और न जाति । उन्हें तो बस शिकार करना है। मक्का -मदीना में सूरजमल के प्रकोप से 500 से अधिक लेगों की जान चली गयी। हमारे देश के अनेक हिस्सों से सुरज कीगर्मी के सामने हथियार डालने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अकेले दिल्ली में एक सप्ताह में 178 लोग गर्मी से अपनी जान गवां चुके हैं। हमारा तमाम ज्ञान -विज्ञान सूरजमल के प्रकोप से अवाम को बचा नहीं पा रहा। हमारे पास अब कोई आसरा नहीं बचा है।

आपको बता दू कि सूरज यानि सूरजमल सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूरजमल का व्यास लगभग 14 लाख हजार किलोमीटर है अर्थात हमारी पृथ्वी से 13 गुना तवक बड़ा है। अब तक की खोज बताती है कि ऊर्जा का यह शत्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है ।परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुँचता है जिसमें से मात्र 15 फीसद अतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है 30 फीसदी पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड पौधे समुद्र सोख लेते हैं। पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8 मिनट से कुछ घड़ी ज्यादा का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश-संश्लेषण नामक एक महत्वचपूर्ण जैव-रासायनिक अभिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है।

कल्पना कीजिये की यदि प्रकाश और ऊष्मा कि आने की ये रफ्तार जरा और बढ़ जाये तो क्या होगा? ध्यान देने योग्य बात ये है कि सुरजमल आज सबसे अधिक स्थिर अवस्था में अपने जीवन के कंरीबन आधे रास्ते पर है। इसमें कई अरख वर्षों से नाटकीय रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ है, और आगामी कई वर्षों तक यूँ ही अपरिवर्तित बना रहेगा। हालांकि, एक स्थिर हाइड्रोजन-दहन काल के पहले का और बाद का तारा बिलकल अलग होता है। जबकि हमने अपनी धरती को बरी तरह से न सिर्फ तबाह कर दिया है। बल्कि उसे पूरी तरह से बदल डाला है। हमने उसके जंगल काट दिए है। हमने उसकी कोख को खंगाल दिया है। हमारी धरती सुरजमल के सामने एक बीमार ग्रह बनकर रह गयी है, लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं है। हम सुरजमल के ताप का मुकाबला करने के लिए नए जांगल लगाने और पुराने जंगलों का संरक्षण करने कि बजाय हर दिन एयर कडीशनर, कूलर और पंखों का उत्पादन बढते जा रहे हैं जो हमने घर के भीतर तो कृत्रिम शीतलता प्रदान करते हैं लेकिन बाहर पहले से तप रही धरती को और तपा रहे हैं। यानि हम उस कालिदास की तरह हैं जो जिस डाल पर बैठा है उसे ही काट रहा है। भक्का में गर्मी से मरने वालों कि शव सड़कों पर पड़े देखकर मन विचालित हो नहीं हुआ बल्कि आत्मा कांप गयी। आप कल्पना कीजिये जब मनष्यों का ये हाल है तो पशु पक्षियों की क्या दशा होगी जो न अपना मकान बनाते हैं और उनके पास एसी.कूलर या पंखे होते हैं। वे सूरजमल की ताप का मुकबला सीधे करते है। हम मनुष्यों ने तो उनके हिस्से की छांव भी छीन ली है। हम स्वार्थी लोग हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में जहां आज भी 85 करोड लोग मात्र 5 किलो अन्न के ऊपर अपना गुजर कर रहे हैं वे गर्मी से बचने कि लिए कैसे संघर्ष करते होंगे? इस आधी आवादी कि पास जब दो जून की रोटी नहीं जुगाड़ सकती तब गर्मी से बचने कि लिए एसी,कूलर और पंखे तो छोड़िये छते तक लेना उनके लिए कल्पनातीत है।

रीतिकाल कि प्रमुख कवियों में से एक सेनापति ने सूरजमल के ताप और प्रकोप को लेकर सैकड़ों साल पहले जो कुछ लिखा वैसा ही आज भी हो रहा है। सेनापति लिखते हैं -

'बृष को तरनि तेज, सहसौ किरन करि,
ज्वालन के जाल बिकराल बरसत हैं।
तपति धरनि, जग जरत झरनि, सीरी
छाँह कौ पकरि, पंथी-पंछी बिरमत हैं॥
श्सेनापति नैक, दुपहरी के ढरत, होत
घमका बिषम, ज्यौं न पात खरकत हैं।
मेरे जान पौनों, सीरी ठौर कौ पकरि कौनौं,
घरी एक बैठि, क घामै बितवत हैं।

कहने का आशय यह है कि ये जो सूर्यकोप है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हमें ही अपने आपको बदलना होगा। हमें घरों में एसी, कूलर और पंखे लटकाने कि बजाय अपने आसपास नए पौधे रोपने होंगे और पुराने सैकड़ों वर्ष पुराने विटपों को जान की कीमत पर कटने से, गिरने से बचना होगा। हमें अपना लालच छोड़ना होगा, यदि ऐसा न हुआ तो जो आज मक्का में हआ है वो दनिया के हर उस हिस्से में होगा जहां उसकी हरीतिमा छीनकर धरती को नग्न किया जा चुका है या किया जा रहा है । ये काम का२ई सरकार, कोई कानून नहीं कर सकत। ये काम आपको, हमको ही करना पड़ेगा। ईश्वर भी हमारी मदद के लिए नहीं आने वाले।

कसिली फीडर पर संविदाकर्मी का शव रख परिजनों ने किया प्रदर्शन

बरहज/मगहरा (देवरिया)। देवरिया क्षेत्र के कसिली-सतरांव विद्युत निगम कार्यालय पर गुरुवार को महुआबारी निवासी और संविदा लाइनमैन अजीत प्रसाद (42 वर्ष) पुत्र सुखदेव प्रसाद का शव रखकर परिजनों ने विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। कुछ देर के लिए आपूर्ति भी ठप कर दी गई थी। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन माने। बरहज के महुआबारी निवासी अजीत प्रसाद का महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जहां रास्ते में उनकी मौत हो गई। अजीत की मौत की जानकारी होने पर घर में कोहराम मच गया। लोग उनका शव लेकर उपखंड कार्यालय पर पहुंच गए। जहां विभागीय लापरवाही से हुई मौत का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने लगे। परिजन एस्-ाएसओ और अधिकारियों को कसूरवार ठहरा रहे थे। जानकारी होने पर एसडीएम अंगद यादव, सीओ आदित्य कुमार गौतम, एसडीओ-टू राधेश्याम चौहान, इंस्पेक्टर राहुल सिंह और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। करीब ढ़ाई घंटे तक मान-मनौव्वल के बाद परिजन माने। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। अजीत कसिली विद्युत निगम कार्यालय में संविदा पर लाइनमैन का काम करते थे। लोगों के अनुसार वह नौ जून को शटडाउन लेकर परसियां भगवती में जंफर जोड़ रहे थे। इसी बीच आपूर्ति बहाल हो गई। जिससे वह बुरी तरह से झुलस गए थे। एसडीओ राधेश्याम चौहान ने बताया कि उच्चाधिकारियों से बात कर पत्नी को नौकरी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। घटना की जांच कराई जाएगी।

भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय आपातकाल

सिद्धार्थनगर(जीकेबी)। 25 जून, 1975 को देश में आपातकाल लगाए जाने की बरसी को मंगलवार को भाजपा ने काला दिवस मनाया। जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान की अगुवाई में नेताओं व कार्यकताओं ने सनई चौराहे से पार्टी के जिला कार्यालय तक पैदल मार्च किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आपातकाल लगाया था। आपातकाल का विरोध करने वाले विपक्ष को कुचलने के लिए जिस तरह से सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया, वह बाबा साहेब के संविधान का भी अपमान था। सत्ता और अपने हित के लिए कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा। संविधान में संशोधन कर कांग्रेस ने प्रेस की स्वतंत्रता छीनने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और संविधान दोनों सुरक्षित हैं। विधायक राजा जय प्रताप सिंह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इस काले इतिहास को याद रखना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतिहास ही वह माध्यम है, जिससे प्रेरणा लेकर वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान ने कहा कि 25 जून, 1975 की आधी रात को लागू किया गया आपातकाल 21 मार्च, 1977 तक लागू रहा। इस अवधि के दौरान सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। कांग्रेस को अपने पूर्व के इतिहास को याद करने की जरूरत है।

इस दौरान जिला प्रभारी हरि चरण कुशवाहा, बृजबिहारी मिश्रा, लालजी त्रिपाठी, विपिन सिंह, विजयकांत चतुवेर्दी, दीपक मौर्य, तेजू विश्वकर्मा, फतेबहादूर सिंह, अजय उपाध्याय मौजूद रहे।

पेयजल की आस रह गई अधूरी, दो साल से बाट जोह रहे ग्रामीण

सिद्धार्थनगर (जीकेबी)। खेसरहा विकास क्षेत्र के मटियरिया गांव में जल जीवन मिशन के तहत दो वर्ष शुरू हुए पानी प्लांट का निर्माण हो जाने के बाद भी अब तक गांव वालों के घरों में पानी नहीं पहुंच सका है। निर्माण के दौरान ही पानी की सप्लाई के लिए सड़कें खोद कर पूरे गांव में पाइप लाइन भी बिछा दी गई थी, लेकिन सप्लाई फेल हो जाने के कारण तीन हजार की आबादी भीषण गर्मी में भी पेयजल की किल्लत से जूझने को मजबूर है।

गांव में हर घर जल पहुंचाने के लिए बने वाटरहेड टैंक से गांव के कई टोलों में पानी की सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच रही हैं। भीषण गर्मी के कारण अधिकतर घरों के नल सूख गए हैं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। वहीं, दूसरी तरफ पंपहाउस के बगल में पानी टंकी बनाने के लिए कई महीनों पहले एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे पंप हाउस के लिए बने कमरे की नींव कमजोर हो रही है। गांव के राम लगन, पुदीन, मनिराम, छोटू, हरिराम, रतन सिंह आदि ने गांव में हर घर तक पेयजल सप्लाई की मांग की है।

इस संबंध में बीडीओ विजय सिंह का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं है, मौके का मुयाअना करा कर शीघ्र ही लोगों के घरों तक पेयजल पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा।

गांव के कई मोहल्लों में पानी की सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच रही है। समय से व्यवस्थित तरीके से निर्माण किया गया होता तो ऐसी समस्या नहीं आती।

पानी की सप्लाई शुरू न होने से पेयजल की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, कोई भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
- राम बेलास, ग्रामवासी

-भीषण गर्मी में जलस्तर नीचे चला गया है, घरों में लगे नल से पानी नहीं आ रहा है। मजबूरन लोग दूषित जल पीने को मजबूर हैं।
- राम भोग, ग्रामवासी

पूर्ति निरीक्षक ने किया राशन की दुकान का निलंबन

निचलौल(जीकेबी)। ब्लॉक क्षेत्र के भारत नेपाल सरहद से सटे बहुआर कला गांव में राशन की कालाबाजारी करने पर पूर्ति निरीक्षक ने कोटे की दुकान निलंबित कर दिया।कोटेदार से 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है।

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर राशनकार्ड धारकों ने 21 जून की रात में अंगूठा लगवाने के दौरान ई-पॉस मशीन लॉक होने पर हंगामा किया था। जानकार सूत्र बताते हैं कि ई-पॉस मशीन लॉक होने पर किया हंगामा शीर्षक से खबर प्रकाशित किया था। मामले का संज्ञान लेते हुए विभागीय अधिकारियों ने जांच टीम गठित कर दी थी। जांच में राशन की कालाबाजारी करने सहित अन्य बिंदुओं पर दोषी मिलने के बाद टीम ने कोटे की दुकान पर 23 जून को नोटिस चस्पा की थी। 24 को टीम ने जांच प्रकिया पूरी करने के बाद कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी थी। पूर्ति निरीक्षक ने रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को कोटे की दुकान को निलंबित कर 15 दिनों के भीतर दुकानदार से सटीक जवाब मांगा है। निचलौल पूर्ति निरीक्षक इंद्रभान ने जारी आदेश पत्र में कहा है कि अमर उजाला अखबार में प्रकाशित खबर के बाद कोटे की दुकान पर पहुंचकर जांच करने के साथ ही राशनकार्ड धारकों के बयान दर्ज किए गए। राशनकार्ड धारक कमरुल, नर्वदा, कृष्णा, मनीरून, किरन, गुड्डी, रीमा, रितू, लिलावती सहित आदि ने सामूहिक बयान दिया कि सभी का उचित दर विक्रेता की ओर से ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगवाकर पर्ची दे दिया गया है, जबकि उन्हें राशन नहीं मिला। कोटेदार की ओर से कहा गया कि अभी राशन नहीं है, जब राशन आएगा तब दे दिया जाएगा। यही समस्या हर माह रहती है। कोटेदार की ओर से अंगूठा लगवाकर राशन नहीं दिया जाता है, जबकि शासनादेश के अनुसार कार्डधारकों का ई-पॉस मशीन पर फिंगर लगने के तुरंत बाद खाद्यान्न का वितरण करने का प्राविधान है। इतना ही नहीं जांच के समय पाया गया की कार्डधारकों से ई-पॉस मशीन पर फिंगर लगवाने के बाद राशन नहीं दिया जाता है। फिंगर लगने के बाद राशन कार्डधारकों को पर्ची देकर यह कहा जाता है की अभी राशन नहीं है, राशन आने के बाद दिया जाएगा। कार्डधारकों को राशन के लिए दौड़ाया जाता है। राशन वितरण में घटतौली की जाती है।

दुकान पर किसी भी प्रकार का स्टॉक बोर्ड और साइन बोर्ड प्रदर्शित नहीं किया गया है। दुकान पर अंत्योदय कार्डधारकों की सूची, टोल फ्री नंबर प्रदर्शित नहीं किया गया है। वितरण रजिस्टर नहीं बनाया गया है। राशन कार्डों पर मात्रा नहीं प्रदर्शित की गई है। राशनकार्ड धारकों से अभद्र व्यवहार किया जाता है।

ऐसे में चंपा देवी उचित दर विक्रेता गांव बहुआर कला की कोटे की दुकान का अनुबंध पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं दुकानदार को अप्रैल, मई व जून के स्टॉक व वितरण अभिलेखों, साक्ष्यों को 15 दिनों के अंदर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। फिलहाल राशनकार्ड धारकों की सुविधा के लिए बहुआर कला के कोटे की दुकान को हिरामन यादव उचित दर विक्रेता गांव बहुआर खुर्द की दुकान से उठान और वितरण संबद्ध कर दिया गया है।

लोगों को नशा नहीं करने के लिए किया जागरूक

पडरौना (जीकेबी)। उदित नारायण इंटर कॉलेज से बुधवार को 50 उत्तर प्रदेश वाहिनी एनसीसी की तरफ से नशामुक्ति अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें लोगों को किसी भी तरह नशा नहीं करने के लिए जागरूक किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल वानामाला कृष्णा ने कहा कि किसी भी प्रकार का नशा व्यक्ति को आर्थिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बना देता है। रैली को रिसालदार मेजर हरपाल सिंह, एएनओ लेफ्टिनेंट राजीव यादव, हवलदार छब्ब बहादुर थापा आदि ने संबोधित किया। इसके बाद एनसीसी कैडेटों ने नशामुक्ति के लिए शपथ ली। इस दौरान सचिन गोंड, प्रभाकर मिश्र, आकाश यादव, पवन यादव आदि मौजूद रहे।

बाढ़ के समय कई गांव जलमग्न हो जाते हैं

सिद्धार्थनगर(जीकेबी)। पिछले वर्षों में भयावह बाढ़ की त्रासदी झेल चुके जिले के लोग मानसून नजदीक आते ही सहमे दिख रहे हैं। सभी पांचों तहसीलों में बहती छह पहाड़ी नदियों व नालों के उफान से बचाव के मुकम्मल इंतजाम नहीं होने से यहां के लोगों को एक बार फिर से सांसत झेलना तय है। बाढ़ से बचाव के लिए नदियों के किनारे बने 39 बंधो में कई के अधूरे होने और कटान स्थलों पर मरम्मत नहीं होने से जिले में एक बार फिर से तबाही मचनी तय है। शाहपुर डुमरियागंज बांध के गैप नहीं भरे जाने से आसपास के ग्रामीण बारिश के मौसम में भयग्रस्त रहते हैं। जिले में नेपाल से निकलने वाली राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कूड़ा, घोघी, बानगंगा नदियों के उफान से हर वर्ष तबाही मचती है। बाढ़ की त्रासदी से बचाव के लिए जिले में 454 किमी लंबे बांध का निर्माण हुआ है। इनमें बांसी-डुमरियागंज बांध में कई लंबे गैप है जिस कारण आसपास के ग्रामीण बाढ़ आने पर जन और धन हानि की आशंका से डरे हुए हैं। जानकारों के अनुसार, डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में राप्ती नदी तट पर बने 40 किमी लंबे शाहपुर से भोजपुर बांध निर्माण कार्य अधूरा है। इसमें कई जगह गैप बरकरार हैं। दो वर्ष पूर्व जिन जगहों पर गैप भरकर निर्माण पूर्ण होने का दावा विभाग कर रहा है, वहां निर्माण के बाद आए बाढ़ में बांध का कुछ हिस्सा कटकर राप्ती में समा चुका है। वहीं शाहपुर से पेड़ारी गांव के बीच अब भी बांध पर दरार है। साथ ही बांध पर जगह-जगह बारिश और चूहे के कारण होल व गड्ढे बने हैं।

पकड़ी बाजार प्रतिनिधि के अनुसार, शोहरतगढ तहसील क्षेत्र बानगंगा नदी बरैनिया गांव के सटे बंधे पर सिंचाई विभाग द्वारा ठोकर बनाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन थोड़ी दूरी पर बैदौली एवं बरैनिया के बीच बंधे पर पिछले साल जहां पर कटान हो रहा था विभाग उस जगह पर मिट्टी डालकर छोड़ दिया है। वहीं नकाही गांव के पास पिछली बार बाढ़ से हुए कटान की जगह बंधे पर हल्की बारिश में पानी रुक रहा है।

2022 की बाढ़ में हुई थी 18 मौतें

जिले के लोग पिछले कई वर्ष से बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। सर्वाधिक तबाही 1998 की बाढ़ में मची थी। जिसमें जिले के 2400 से अधिक गांव में से 1653 गांव मैरूंड हो गए थे। इस बाढ़ में डूबने से 52 मनुष्यों एवं 481 पशुओं की मौत हो गई थी। इसमें 1.90 लाख हेक्टेयर भूमि जलमग्न और सात लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। इसके बाद वर्ष 2022 में भी बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई। इसमें 18 लोगों की मौत हुई थी और पांच लाख लोग प्रभावित हुए थे। इस वर्ष कई बांधों के टूटने से 60 हजार हेक्टेयर भूमि पांच सौ गांव जलमग्न हो गए थे।

यह बांध हैं अधूरे

जिले की पांचों तहसीलों में 454 किमी लंबे 39 बांधों में कई जगह गैप होने से ग्रामीण सहमे हुए हैं। राप्ती नदी के बाएं तट पर बने बांसी-डुमरियागंज बांध में कई गैप है। इसमें बांसी तहसील क्षेत्र में एक-एक किमी लंबे दो गैप है, जिसके भरे नहीं जाने के कारण बाढ़ के समय कई गांव जलमग्न हो जाते है। इसी तरह भोजपुर-शाहपुर बांध, छगड़िहवा-सोनबरसा बांध और फत्तेपुर-खजुरडाड़-अजगरा बांध में गैप होने से भी कई गांव पर खतरा रहता है। बांसी डुमरियागंज बांध में गैप भरने के लिए ग्रामीणों ने कई बार विभागीय अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।

अतिक्रमण हटाने पहुंचे नायब तहसीलदार से नोकझोंक

पडरौना,कुशीनगर (जीकेबी)। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए काश्तकारों से समझौते के आधार पर क्रय की गई जमीन में बने मकानों को तोड़ने को लेकर सोमवार को हंगामा हो गया। मकान ध्वस्त करने का वीडियो बना रहे किशोर पर नायब तहसीलदार भड़क गए और किशोर का मोबाइल ले लिए। यह देख आसपास के लोग पहुंचे गए और इसका पुरजोर विरोध किया। लोगों का तर्क है कि अगर मकान ध्वस्त करने की प्रक्रिया सही है तो वीडियो बनाने और फोटो खींचने का अफसर क्यों विरोध कर रहे हैं? काश्तकारों का तर्क है कि हाईकोर्ट में मामला लंबित है और प्रशासन जबरन मकानों को तोड़ रहा है। जबकि, जिम्मेदार अफसरों का कहना है कि मामला किसी भी कोर्ट में लंबित हो, जब तक कोर्ट का स्थगन आदेश नहीं रहेगा तब तक विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी।

कसया तहसील के भलुही मदारी पट्टी गांव में दोपहर करीब 1:30 बजे नायब तहसीलदार शैलेष सिंह राजस्व टीम के साथ पहुंचे। शशिवाला देवी के मकान को जेसीबी से तोड़वाने लगे। मकान टूटता देख शशिवाला का छोटा बेटा पहुंचा और मकान तोड़ने का वीडियो बनाने लगा। यह देख नायब तहसीलदार नाराज हो गए और किशोर के पास दौड़ते हुए पहुंचे और उसका मोबाइल छीन लिया। यह देख गांव के लोग वहां पहुंच गए और इसका विरोध करने लगे। इसको लेकर गांव वाले और नायब तहसीलदार से

नोकझोंक भी हुई। मामला बढ़ता देख नायब तहसीलदार बैकफुट पर आए और किशोर का मोबाइल वापस तो कर दिया, लेकिन बार-बार लोगों से वीडियो डिलीट कराने की बात कहते रहे। गांव वालों का कहना है कि प्रशासन शुरू से ही मनमानी कर रहा है। नायब तहसीलदार ने दो मकानों का कुछ हिस्सा तोड़वाने के बाद जेसीबी मशीन हटवा दी और दो दिन के अंदर लोगों से निर्माण हटा लेने की माहलत दी। प्रशासन की इस कार्यशैली से गांव वालों में नाराजगी है। नायब तहसीलदार शैलेष सिंह ने बताया कि मुआवजा लेने के बाद जो मकान नहीं हटाए गए हैं, उन्हीं मकानों को हटाने के लिए टीम गई थी। एक मकान था जिसकी खिड़की तोड़ दी गई थी। उस खिड़की को दोबारा लगा दिया गया था। इसी को हटाया जा रहा था। इसका वीडियो एक किशोर बनाने लगा। इसी पर उसको डांटा गया। गृहस्वामियों को दो दिन का मौका दिया गया है।

काश्तकारों और गृह स्वामियों का तर्क

एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भलुही मदारी पट्टी के अलावा आसपास के किसानों की करीब 32 एकड़ जमीन लेने का प्रस्ताव प्रशासन ने सितंबर 2020 में पारित किया। काश्तकारों और गृह स्वामियों ने प्रशासन से मिलकर उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा देने की मांग की है। लेकिन, प्रशासन ने काश्तकारों की मांगों को नजरअंदाज कर समझौते के तहत जमीन का बैनामा करा लिया और मुआवजा भी दे दिया। काश्तकार इससे संतुष्ट नहीं हैं। लोगों का कहना है कि जमीन वर्ष 2020 के बाद ली जा रही है और मुआवजा वर्ष 2011 के सर्किल रेट से दिया गया है जो उचित नहीं है। यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। लेकिन, इधर एक सप्ताह से प्रशासन ने मकानों को तोड़ने की कार-वाई तेज कर दी है। काश्तकारों का कहना है कि हाईकोर्ट ने 30 मई को मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रशासन को चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था, जो इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा।

सामाजिक राजनीतिक चेतना जगाने समर्थ है विष्णु प्रभाकर का रचना संसार

21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले स्थित मीरापुर गांव में जन्में विष्णुप्रभाकर का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उन्हें बचपन से ही लेखन में रुचि थी। विष्णु, विष्णुगुप्त, विष्णुदत्त, और प्रेम-बंधु आदि छद्म नामों से वह कहानियां लिखते थे। साल 1934 में उन्होंने हिन्दी साहित्य की प्रभाकर की परीक्षा पास की और इसके बाद वह अपने नाम के साथ प्रभाकर लगाने लगे। साल 1931 में महज 19 वर्ष की आयु में विष्णु प्रभाकर की पहली कहानी दीवाली के दिन लाहौर के हिन्दी मिलाप में प्रकाशित हो गई थी। लेकिन उनका नियमित लेखन 1934 से शुरू हुआ और इसके बाद फिर उनहोंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महान कथाकार प्रेमचंद ने अपने अखबार और साहित्य पत्रिका हंस में उनकी कहानियां प्रकाशित कीं7 यही नहीं उस दौर की हिन्दी साहित्य की सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं अलंकार, विशाल भारत, सरस्वती, माया, सुधा, माधुरी, कहानी, धर्मयुग आदि में विष्णु प्रभाकर की कहानी छपी और उन पर खूब चर्चा हुई।

विष्णु प्रभाकर ने गद्य की सभी विधाओं में लिखा, लेकिन वह मूल रूप से कहानीकार ही थे। उन्होंने तकरीबन तीन सौ कहानियां लिखीं। धरती अब भी घूम रही है, मुरब्बी, जज का फैसला, अधूरी कहानी मेरा वतन, पुल टूटने से पहले अभाव, ठेका, हिमालय की कहानी उनकी कालजयी कहानियां हैं। विष्णु प्रभाकर की प्रारंभिक कहानियों में शैली और शिल्प की दृष्टि से जैनेन्द्र का काफी प्रभाव था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी भाषा एवं कहानी शिल्प को बदला और अपनी खुद की एक अलग ही शैली निर्मित की, जो पाठकों को बेहर पसंद आई। विष्णु प्रभाकर की बहुचर्चित कहानी धरती अब भी घूम रही है समाज और व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता को बड़े ही खूबसूरती के साथ उकेरती है। बच्चों के पात्रों केजरिए उन्होंने व्यवस्था पर कड़े प्रहार किए हैं। इस कहानी ने विष्णु प्रभाकर को काफी लोकप्रियता दिलाई। कहानी का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। विष्णु प्रभाकर ने हिन्दू-मुस्लिम संबंधों पर कई प्रभावशाली कहानियां लिखी हैं। भारत का विभाजन उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। साम्प्रदायिक दंगों से दो सम्प्रदायों के बीच अविश्वास और दुराग्रह पैदा हुए, इन समस्याओं की शिनाख्त और इनका निराकरण वे अपनी कहानियों के माध्यम से ही करते हैं। अधूरी कहानी, मेरा बेटा, तांगेवाला, मेरा वतन, आदि कहानियों में उन्होंने बंटवारे के बाद के साज और उस-ाकी मनोवैज्ञानिक स्थितियों का मार्मिक चित्रण किया है। यह कहानियां इतनी भावनात्मक हैं कि नफरत भरे दिलों में भी बदलाव ला दें।

विष्णु प्रभाकर का तसव्वुर करो तो एक तस्वीर जेहन में चली आती है। सिर पर गांधी टोपी, और शरीर पर खद्दर का कुर्ता-पायजामा, बकिस्ट। एक गांधीवादी लेखक जो सादगी की जीती जागती मिसाल थे। उन्होने न सिर्फ अपने जीवन में गांधीवादी जीवन मूल्यों को अपनाया एवं उनके आदर्शों पर चले, बल्कि अपनी रचनाओं में भी इस विचारधारा को प्रतिष्ठित किया। प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार की तरह विष्णु प्रभाकर ने भी अपने साहित्य से गांधी चिंतन को ठोस व्यवहारिक रूप प्रदान किया। विष्णु प्रभाकर का साहित्य लोगों में सामाजिक चेतना जगाने का काम करता है। खासतौर से महिलाओं के लिए उन्होंने खूब साहित्य रचा। उनकी समस्याओं एवं परेशानियों को साझा और उन्हें अपनी आवाज दी। अपनी कहानी कला के बारे में विष्णु प्रभाकर का कहना था, मैं न आदर्शों से बंधा हूं और न सिद्धान्तों से। बस भोगे हुए यथार्थ की पृष्ठ भूमि में उस उदात्त की खोज में चलता चला आ रहा हूं। मेरे पास वह कला भले न हो जो कहानी को कहानी बनाती है पर झूठ का सहारा मैंने कभी नहीं लिया।

विष्णु प्रभाकर ने साहित्य की तकरीबन सभी विधाओं कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, संस्मरण, यात्रा-वृत्तांत, बाल कहानियां, बाल नाटक, अनुवाद, विचार-निबंध, आदि में जमकर लिखा। उनकी किताबों की संख्या सौ से ऊपर है। देश-विदेश की कई भाषाओं में इन किताबों का अनुवाद हुआ है। विष्णु प्रभाकर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जो तीन खंडों में है। जिंदगी की इब्तेदा में कुछ साल सरकारी नौकरी करने के बाद वह हमेशा मसीजीवी ही रहे। पूर्णकालिक लेखक के तौर पर ही उन्होंने काम किया। सिर्फ लेखन भर से उन्होंने अपना और अपने परिवार का गुजारा किया। विष्णु प्रभाकर ने आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र पर नाट्य निर्देशक के रूप में भी कार्य किया। रेडियो में काम करने के दौरान उन्होंने कई रूपक एकांकी और नाटक लिखे। जिनका रेडिया से तो प्रसारण हुआ ही, बाद में किताब के रूप में प्रकाशित हुए स्कूल-कॉलेजों की पाठ्य-पुस्तकों में उन्हें शामिल किया गया। नया कश्मीर और लालकिला विष्णु प्रभाकर के न भुलाए जाने वाले रूपक और स्वराज की नींव, युगे-युगे क्रांति, जज का फै सला श्वेत कमल, युग-संधि, प्रकाश और परछाईं, नव प्रभात, कुहासा और किरण आदि चर्चित एकांकी नाटक हैं। इन रूपक और एकांकियों में उन्होंने अनेक विषयों जनशिक्ष प्रौढ़ शिक्षा देश के स्वतंत्रता आंदोलन और स्त्रियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उभारा। उनकी एकांकी सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई हैं और श्रोताओं पाठकों में सामाजिक राजनीतिक चेतना जगाने का काम करती हैं। उन्हें शिक्षित करती हैं।

विष्णु प्रभाकर ने जैनेन्द्र, यशपाल, अश्क, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, की पीढ़ी से लेकर कमलेश्वर, अमरकांत, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, और बाद की पीढ़ी दूधनाथ सिंह, ज्ञानरंजन, शेखर जोशी, राजेन्द्र यादव, रवीन्द्र कालिया, और काशीनाथ सिंह के साथ लेखन किया और अपनी अलग पहचान बनाए रखी। विश्णु प्रीााकर एक महतवपूर्ण कार्य बांग्ला भाषा के चर्चित रचनाकार शरतचंद चट्टोपाध्याय की जीवन आवारा मसीहा लिख है। यह उपन्यासपरक जीवनी है, जिसे उन्होने चौदह साल के गहन शोध के बाद लिखा था। यह जीवनी इतिहास और उपन्यास का मिश्रण है। शरतचंद्र के जीवन और लेखन से जुडे तथ्यों को उन्होंने रोचक भाषा और शैली में इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि यह जीवनी उपन्यास होने का आभास और रस देता है। आवारा मसीहा ने विष्णु प्रभाकर को खूब लोकप्रियता दिलाई। हिन्दी में इस स्तर की प्रमाणिक जीवनियां बहुत कम लिखी गईं हैं। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के अलावा विष्णु प्रभाकर ने और भी शिखर व्यक्तित्वों पर छोटी-छोटी जीवनियां लिखीं। इनमें प्रमुख हैं- स्वामी दयानन्द सरस्वती, सरदार बल्लभ भाई पटेल, गांधी वादी काका कालेलकर, शहीद भगत सिंह, अहिल्याबाई होल्कर, बंकिम चंद्र चटर्जी, और कमाल पाशा।

विष्णु प्रभाकर ने बच्चों के लिए काफी बाल साहित्य लिखा। वह बाल साहित्य को बहुत गंभीरता से लिया करते थे और महत्वपूर्ण मानते थे। क्योंकि बच्चों के बालमन पर इसका गहरा असर होता है। बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए उन्होंने उनके लिए ढेरों मनोरंजक कहानियां और नाटक लिखे, जिसमें मनोरंजन के साथ-साथ वह उनको शिक्षा भी देते थे। बच्चों की पत्रिका पराग में उनके बाल उपन्यास गजानन्दन लाल का धारावाहिक प्रकाशन हुआ, जिसे बाल पाठकों के बीच खासी लोकप्रियता मिली। कहीं कुछ नहीं बदला, सबसे सुन्दर लड़की, धन्य है आपकी परख, बाबू जी बरात में, अबदुल्ला, आदि उनकी प्रमुख बाल कहानियां हैं। वहीं सुनो कहानी के दो खंडों में उनकी कई मजेदार कहानियां संकलित हैं। हिन्दी साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए विष्णु प्रभाकर कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किए गए। उपन्यास अर्द्धनारीश्वर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो भारत सरकार ने पद्मभूषण राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। पाब्लो नेरूदा सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार, हिन्दी अकादेमी शलाका सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेरू पुरस्कार उनहें मिले कुछ सम्मान हैं। विष्णु प्रभाकर को एक लंबी जिंदगानी मिली। उन्होने समय के एक लम्बे काल खंड को देखा, उसे आत्मसात किया ओर उसे प्रभावी ढंग से अपने लेखन में उतारा। अपने सात दशक के लेखन में कई अविस्मरणीय कहानियां और पात्र दिए। जिन्हें भूलना नामुमकिन है।

अध्ययन

खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति अधिक असमंजस वाली

मुंबई। कोविड महामारी के बाद आर्थिक पुनरुद्धार को दर जिस तरह से अलग - अलग थी उसी तरह मुद्रास्फीति भी है। इसने कुछ सबके अन्य के रहे हैं। विदेशी ब्रोकरेज कंपनी एच एस बी सी के अर्थशास्त्रियों के अनुसार, शहरी उपभोक्ताओं के मुकाबले महंगाई से ग्रामीण उपभोक्ता अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उन्हेंने अपनी रिपोर्ट में कहा जिस तरह अर्थ व्यवस्थाओं के आकार का पुनरुद्धार देखने को मिला था उसी प्रकार की स्थिति मुद्रा स्फीति के मामले में देखने को मिल रही है।

एच एस बी सी की मुख्य अर्थशात्री प्रांजल भंडारी ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा भीषण गर्मी का हवाला दिया है। जो यह बताता है कि एक तरफ जहां वाद्य वस्तुओं की महंगाई ऊंची है वहीं मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति में जवमी की स्थिति भी है। इसका कारण फसल को नुकसान और पशुधन मृत्युदर है। मुख्य मुद्रास्फीति में खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों के प्रभाव को शामिल नही किया जाता है। सरकार ने ईंधन की मलों में कटौती करके मदद का हाथ बढ़ाया है लेकिन आमतौर पर गांवो में पेट्रोल डीजल एलपीजी का उपयोग शहरों की तरह नहीं होता। इसके कारण ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी की तुलना में अधिक है। इसमें कहा गया है कि खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति अधिक असमंजस वाली लगती है। क्योकि आदर्श रूप से हर किसी के मन में आएगा कि जब खाद्यान्न का उत्पादन जांवों में होता है तो वहां शहरों की तुलना में महंगाई कम होना 'चाहिए' इसके कारण किसानों की आय को नुकसान हुआ।

खरीददारों को खाद्य पदार्थ बेचने के लिए अधिक प्रयास कर रहे हैं। इससे रिटर्न अधिक हो सकता है, लेकिन इसके कारण उनके क्षेत्रों में आपूर्ति कम रह जाती है जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं।

साथ ही शही योगों में बंदरगाहों से खाने की मेज तक सामान पहुंचाने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा है। उससे भायादि वस्तुओं की कीमते काम करने में मदद मिलती है।

यहां की आवोहवा, बढ़ता जा रहा सारसों का कुनबा

कुशीनगर(जीकेबी)। कुशीनगर जिले की आबोहवा राजकीय पक्षी सारस को भा रही है। तभी तो इनका कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल जिले में 44 सारस थे, जिसमें 41 व्यस्क और तीन बच्चे थे, लेकिन इस साल यह संख्या बढ़कर 50 हो गई है। इन दिनों सारस खेतों, नमी वाले क्षेत्रों में समूह बना कर चुग रहे हैं। वन विभाग ने इसके संरक्षण के लिए पहल तेज कर दी है। राजकीय पक्षी सारस के संरक्षण के लिए शासन स्तर से पहल की जा रही है। हर साल सारस पक्षियों की गणना होती है। जिले में पिछले साल 44 सारस थे। इस साल इनकी संख्या 50 हो गई है। वन विभाग ने वन कर्मियों व ग्रामीणों के जरिये सारसों की गणना की। अब इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन शासन को भेजी जाएगी। साथ ही वन विभाग के सभी कर्मचारी सारसों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। सारस गणना की रिपोर्ट वन विभाग शासन को सौंपेगा।

काव्य गोष्ठी का हुआ आयोजन

नई दिल्ली। दिल्ली सुर साहित्य परिषद् एवं टू मीडिया के तत्वावधान में टू मीडिया शालीमार गार्डन, गाजियाबाद में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक सुर साहित्य परिषद् के संस्थापक डॉक्ट्र संजय जैन जी (दिल्ली सरकार में उच्चाधिकारी, लब्धप्रतिष्ठित शायर) रहे। स्वागतकर्ता के रूप में टू मीडिया संस्थापक एवं सुर साहित्य परिषद् के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी डॉ. ओमप्रकाश प्रजापति जी की उपस्थिति रहीं।

दिल्ली आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिकारी राम अवतार बैरवा कार्यक्रम अध्यक्ष रहे, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति रहीं। शायरा, संचालिका, मोटीवेशनल स्पीकर एवं साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था अंतस की संस्थापिका डॉ. पूनम माटिया, विशिष्ट अतिथि रहे। ललितपुर बुंदेलखंड खंड से पधारे मशहूर शायर डॉ ट्र कौशल सोनी फरहत मंच संचालन सुर साहित्य परिषद् की महामंत्री उर्वी ऊदल जी ने किया। आमंत्रित अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के पश्चात डॉ ट्र मीनाक्षी भसीन जी के द्वारा मां शारदे की वंदना की गई। काव्य गोष्ठी में सुर साहित्य परिषद् के पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। सचिव - नयन नीरज नायाब, कोषाध्यक्ष - अनुराधा पाण्डेय, उप सचिव - डॉ. सत्यम भास्कर जी एवं मीडिया प्रभारी श्रीमती सीमा रंगा जी की उपस्थिति रही, आप सभी ने आमंत्रित अतिथियों का सम्मान किया एवं कार्यक्रम को सुचारु रूप से सम्पन्न कराने में सक्रिय भूमिका निभाई। इस अवसर पर दिल्ली एवं दिल्ली के बाहर के काव्य रथियों की उपस्थिति रहीं अपर्णा थपलियाल जी उत्तराखंड, भूपेंद्र राघव अंकुर मिश्रा, ज्ञानेन्द्र प्रयागी, हिमांशु शुक्ला, ललित मोहन जोशी, कीर्ति रतन, मनोज डागर, मीनाक्षी भसीन, नईम हिन्दुस्तानी, आरिफ देहलवी, असलम बेताब, प्रत्यूष शर्मा, काशीपुर, अशोक भारद्वाज, अनुभव शर्मा, मेरठ आदि की गरिमामई उपस्थिति रही सभी काव्य रथियों ने अपनी रचनाओं से सभी को सम्मोहित किया गीत, गजल, छंद, नज्म, रुबाई की पुरवाई चली, सभी काव्य रथियों ने काव्य गंगा में डुबकी लगाई। कार्यक्रम के अन्त में डॉ. ओम प्रकाश प्रजापति ने धन्यवाद ज्ञापन किया और कार्यक्रम का समापन किया।

साहित्य दर्शन ई पत्रिका के ग्रीष्मकालीन विशेषांक का विमोचन सम्पन्न

भवानीमंडी। अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान इकाई भवानीमंडी द्वारा प्रकाशित साहित्य दर्शन ई पत्रिका वर्ष 03 अंक 47 ग्रीष्मकालीन विशेषांक का ऑनलाइन विमोचन समारोह में विमोचन किया गया।रविवार को आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि कवयित्री आकांक्षा राठौर ने ऑनलाइन विमोचन किया।कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. राजेश कुमार शर्मा पुरोहित ने की।विशिष्ट अतिथि कवयित्री पूजा गाडुलिया शुभांगी शर्मा (राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित) श्रद्धा तिलवाड़िया रही।-विशेष सानिध्य अतिथि कवयित्री आशारानी जैन आशु व डॉ. गीता दुबे रही। साहित्य दर्शन के प्रधान संपादक ने बताया कि ग्रीष्मकालीन बिशेषांक में 31 रचनाकारों की काव्य रचनाएं चयनित कर प्रकाशित की गई है।ये रचनाएँ राजस्थान मध्यप्रदेश गुजरात उत्तरप्रदेश सहित देश के विभिन्न प्रान्तों के कवि कवयित्रियों द्वारा आमंत्रित की गई थी। इस विशेषांक की रचनाओं में ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग कैसे करें। ग्रीष्म ऋतु का प्रकृति वर्णन, जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण के कारण व निवारण, धरती का बढ़ता तापमान, ग्लोबलाइजेशन।अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने जैसे विषयों पर आधारित रचनाएँ शामिल की गई। कार्यक्रम का संचालन कवयित्री उत्साह जैन ने किया।

ऋतु बरसात की (बाल रचना)

उमड़ -घुमड़ कर बादल आये
पानी की रिमझिम बौछारें लाये
बिजली चमकी, बिजली गरजी
कब तक बरसेगा, बादल की मर्जी
भीग गये सब घर -द्वार
बहने लगी मौसमी शीतल बयार
गुल्लू ने कागज की नाव बनाई
बहते पानी में वह नाव चलाई
फिर खुशी से मनभर चिल्लाया
उसको नाव वाला खेल पसंद आया
ऋतु बरसात की नव जीवन देती
और कीचड़-कीट समस्या भी लाती
उमड़ - घुमड़ कर बादल आये
पानी की रिमझिम बौछारें लाये

मुकेश कुमार ऋषि वर्मा

साहित्य दर्शन ई पत्रिका के ग्रीष्मकालीन विशेषांक की समीक्षा

साहित्य दर्शन ई पत्रिका वर्ष 3 अंक 47 पढ़ा। ई पत्रिका का मुखावरण बड़ा सुन्दर आकर्षक लगा मुझे।ग्रीष्मावकाश में बच्चे जब अपने ननिहाल गाँव मे जाते हैं वहाँ वे गाँव के बाहर हरे भरे खेतों की सैर पर निकलते हैं। उन्हें वहाँ आम से लदे पेड़ नजर आते हैं। गाँव के बच्चे गिलोल से निशाना लगाकर फलों को पेड़ से नीचे गिराकर खाते हैं। ऐसा ही दृश्य इस विशेषांक के मुखावरण पर दिखाई दिया।बच्चों के चेहरे पर कितनी अच्छी मुस्कराहट है। इस विशेषांक में 31 काव्य रचनाएँ है, जिन्हें पढ़कर समीक्षा करने का प्रयास किया है। नवीन श्रीवास्तव ने अपनी काव्य रचना में लिखा-**धरनि तपाती पग जलाती,पथ का डामर पिघलाती है**। जब तेज गर्मी पड़ती है 58 डिग्री तापमान पर डामर पिघलने लगता है। इस साल बहुत तापमान रहा। यथार्थ वर्णन आपने किया। शैलेन्द्र गुनगुना ने गर्मी के दिन हाय हाय शीर्षक से अपनी कविता में स्वदेशी चीजें अपनाने की बात को प्रमुखता से रखने का प्रयास किया है।

मीनाक्षी सुकुमारन नेआगमन ग्रीष्म ऋतु के मे ठण्डी चीजों के सेवन की बात कही वाटर पार्क में जाना आदि।

महावीर प्रसाद जैन जी गर्मी का भी मस्त है हाल रचना में लिखा-

समय और संयम का रखो ख्याल।
जल संरक्षण करो हर साल।।

वाकई जल की एक एक बूँद कीमती है हमें वर्षा के जल का हर वर्ष संचय करना ही चाहिए। राधेश्याम शर्मा लिखते हैं-

आओ बारूदी आग बुझाएं,
आओ सब मिल पेड़ लगाएं।

आज हरियाली की वास्तव में जरूरत है।हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनका संरक्षण करना चाहिए।आ.कमलेश जी ने दूध दही छाछ पीने की बात कही।विदेशी शीतल पेय से बचने की महती जरूरत है।आदरणीय डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा पुरोहित जी ने अपनी काव्य रचना में धरती के बढ़ते तापमान का कारण भूमंडलीकरण बताया।कवयित्री अदिति जी ने **'प्यासी धरती राह निहारे आओ मिलकर हम इसे सँवारे।'** इस रचना के माध्यम से हरी भरी धरा करने की मंशा जाहिर की है।

वरिष्ठ कवि अब्दुल मलिक खान जी ने लिखा꞉लपटों की फसल उगी गर्मी के मौसम में,बफीर्ली प्यास जगी गर्मी के मौसम में के माध्यम से ग्रीष्म ऋतु के कहर को परिभाषित किया है।कवि अश-ाोक सुमन जी ने मायड़ भाषा मे गीत लिखा जो बहुत अच्छा लगा वो लिखते हैं꞉पाणी अमृत सो लागे रे꞉।आ.राकेश थावरिया जी ने वृक्षारोपण का बीड़ा उठाएं,स्वर्ग से सुन्दर धरती बनाएं के जरिए वृक्षारोपण की बात कही है।कवयित्री नीता चौहान जी ने गर्मी के दिन शीर्षक से गर्मी के दिनों में अवकाश के समय मस्ती भरी बातों के बारे मे लिखा।कवि राम चन्दर आजाद जी ने दो कवित्त लिखे।वे लिखते हैं꞉धरती को लगत बुखार हो गया꞉।जैसे बुखार आता है तो रोगी कैसे गर्म हो जाता है उसका बदन तपने लगता है इसी प्रकार धरती तप रही है।आदरणीय बलराम निगम जी ने आठ दोहों की गीतिका लिखी।वे लिखते

हैं꞉कोयलिया कहने लगी,कैसे छेड़ूँ तान।हरियाली दिखती नहीं,धरा लगे शमशान।।आदरणीय सुनील राठौर जी की रचना गर्मी का आघात में कंक्रीट के जंगल प्राकृतिक संतुलन खुदगर्जी में पेड़ काटने जैसी बातों पर अपनी पैनी कलम चलाई है।आदरणीय अरुण गर्ग जी ने उफ गर्मी रचना में गर्मी के तीखे तेवर को बखूबी लिखा है।डॉ. गीता दुबे जी ने गर्मी के बढ़ते कहर को लिखा वे कहती है **स्वार्थ में हरीतिमा धरती को हमने काट दी**। अभिनव ने **आओ वृक्ष लगाएं** कहकर नव चेतना का संचार किया है।

वरिष्ठ कवि दर्शन सिंह ने **गली मोहल्ले प्याऊ लगाई**। जक सेवा जैसे कार्यों की महती आवश्यकता जताई है।

संजय श्रीमाल ने ग्रीष्मकाल (जागो मानव)।आप लिखते हैं-

वृक्ष लगाओ खूब लगाओ।
अब भी वक्त पड़ा है।

आप ऐसा कहकर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु सावचेत कर रहे हैं।

विनोद कहते हैं-

गर्मी का मौसम आया
फूल बाग में मुरझाया है।

आपने सही कहा गर्मी आते ही बाग बगीचों में रौनक खत्म सी हो जाती है। रामप्रीत आनंद ने जेठ की दुपहरी सताती बहुत है बहुत अच्छी रचना लिखी।

राजेन्द्र आचार्य राजन ने अपनी काव्य रचना में आए दिन कट रहे पेड़ों से होने वाले प्रभाव को अपनी काव्य रचना में लिखा है।वे कहते हैं꞉तपती धरती कटती है शाखें। हर जीव अब वृक्षों की ओर झांके। इससे बचने का उपाय वे बताते है कि-

प्रण करें हम सब मिलकर
सबको भीषण गर्मी से बचाएं।

आओ वृक्षोत्सव के शुभ अवसर पर हम सब पेड़ लगाएं।

कवि के.एन..परमार ने धूप शीर्षक से लघु कविता में लिखा-

दूरियों को नजदीकी में बदलती यह धूप।

कविता के माध्यम से मानवीय एकता की बात आपसी भाईचारे की भावना को लिखा है।

डॉ. आदित्य गुप्ता जी ने-गगन से बरस रही आग,कंक्रीट की सड़कें तपती।बढ़ते तापमान को रेखांकित किया है। गीतकार शोभाराम नागर शोभित ने अपने गीत के माध्यम से- **'लगा पेड़ धरा को बचा लो सनम'** कह कर पेड़ लगाने की बात कही।

कवयित्री पूजा गाडुलिया ने प्रकृति को हरी भरी बनाने की कहा। कवयित्री आकांक्षा कहती है पोखर सारे सुख गए मानव के शोषण से।लौटेगी फिर हरियाली केवल वृक्षारोपण से। आपने भी वृक्ष लगाने व संरक्षण की बात लिखी। कवयित्री नम्रता जैन जी ने जिओ और जीने दो, लक्ष्य हमारा हो हरदम कहकर जीव मात्र पर दया करने की बात कही। आज मनुष्य स्वर्थवश जंगल काट रहा है।जिसके कारण जंगली जानवरों के वास स्थान खत्म हो रहे हैं।वन्य जोवों पशु पक्षियों की कई प्रजातियां लुप्त होती जा रही है।

सारांश में कहूँ तो सभी रचनाकारों की रचनाएं श्रेष्ठ हैं। यह विशेषांक गागर में सागर जैसा है। कई प्रकार की जानकारियों का इसमें खजाना छिपा है।

शुभांगी शर्मा (बाल कवयित्री)
भवानीमंडी जिला झालावाड़ (राजस्थान)

बी ग्रेड की फिल्मों की नायिका सिल्क स्मिता

भारतीय सिनेमा में हर दिन एक नई फिल्म की कहानी आती है। 1 साल में न जाने कितनी फिल्में रिलीज हो जाती है और उन फिल्मों के साथ आते हैं ना जाने कितने चेहरे के में कुछ तो दर्शकों की पसंद बन जाते हैं और कुछ सिने प्रेमियों को बिल्कुल कवारा नहीं होते और जल्दी ही फिल्मी दुनिया से ओझल हो जाते हो लेकिन सिनेमा जगत के कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने कई सालों तक दर्शकों के दोनों कहीं गायब हो गए किसी कि इस गुमनामी को बड़ा नाम मिला तो किसी को मौत का।

सिर्फ का असली नाम विजयलक्ष्मी उर्फ सिल्का जैन था। सिल्क का परिवार शुरू से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था जब सिलका पैदा हुई उस वक्त इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि दिन वह फिल्म में वह नाम कामाएगी। आर्थिक तंगी का आलम यह रहा की चौथी कक्षा के बाद ही उन्हें शिक्षा से दूर कर दिया गया और उनके ऊपर घर के चूहे चौक की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सिल्क अब धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी और उनके शरीर में उभर रहा परिवर्तन मर्दो की पसंद बनता जा रहा था उन्हें प्रभावित कर रहा था जिसे देखते हुए सिल्क की मा ने उसकी शादी करना ठीक समझा। और एक बैल गाड़ी वाले के साथ उनकी शादी तय कर दी। लेकिन ससुराल में भी वह खुश ना रह सकीं। उनके पति वह ससुराल वालों की आए दिन नई-नई सरसों व इच्छाओं से वह तंग आ चुकी थी जिसके बाद उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया। सिल्क अपना ससुराल वह पति छोड़कर चेन्नई आ गई। और यहां आकर एक छोटी एक्ट्रेस के घर में बतौर नौकरानी काम करने लगी। धीरे-धीरे सिल्क इस एक्ट्रेस के मेकअप आर्टिस्ट बन गई। एक दिन उसे एक्ट्रेस के घर में एक बड़े जाने-माने निर्माता का आना हुआ उनकी गाड़ी देखकर सिल्क काफी प्रभावित हुई इस पर उसकी मालकिन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि क्यों ऐसी गाड़ी देखकर इसमें बैठने के सपने देखने लगी हो। क्या बात सिल्क के दिल को और उन्होंने पलट कर जवाब में कहा एक दिन जरूर बैठूंगी और वह मेरी खुद की गाड़ी होगी। इस वाकये के बाद सिंफनी सोच लिया कि वह इस दुनिया को अपने काबिलियत का नमूना दिखा कर रहेगी सांवला रंग नशीली आंखें उन्हें फिर मैं छोटे मोटे रोल दिलाने में अपना काम करने लगी। धीरे-धीरे सिल्क प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पहली पसंद बनती जा रही थी आलम यह था की फिल्म में सिल्क का एक गाना होना तो जैसे दक्षिण भारतीय फिल्मों का रिवाज बनता जा रहा था। इतना ही नहीं और अगर कोई फिल्म बहुत समय से बनी हुई हो लेकिन रिलीज में डाउट हो तो उसमें एक सिल्क कर गाना डाल दिया जाता था। सिल्क बी ग्रेड की फिल्मों की पहचान बन चुकी थी भरा पूरा शरीर और उनकी अदाएं काफी थी दर्शकों को थिएटर तक खींचने के लिए। साल 1979 में आई मलयालम फिल्म इनडिथेडी मैं उन्हें बड़ा रोल ऑफर किया गया। उसे दौर में सिल्क की सेक्स अपील को बढ़ाने के लिए फिल्मों में उनका कैबरे डांस डाला जाने लगा। सिल्क कभी भी फोन स्क्रीन एक्सपोज करने से कटरा ही नहीं उनके अंदर हीरोइन बनने की इतनी चाहत थी कि उन्होंने अपनी कुदरती खूबसूरती को पर्दे पर दर्शकों को निभाने के लिए इस्तेमाल करने में एक बार भी संकोच नहीं किया। इसके बाद आई उनके दूसरी फिल्म बंडी चक्रम जो की एक तमिल फिल्म थी उसने दर्शकों को हिला कर रख दिया इस फिल्म में उन्होंने एक शराब की दुकान चलाने वाली लड़की की भूमिका निभाई जो कि अपने अंदाज हुआ लटके झटको से सबको अपना दीवाना बना रही थी। सिल्क का रंग रूप और अदाएं देखकर दर्शक उनके लिए पागल होते जा रहे थे। दक्षिण भारत की फिल्मों में प्रदर्शित उनका डांस और भी फिल्मों की पहचान बनती जा रही थी सिर्फ उसे दौर में एक गाने के 50 हजार रुपए की कर मोटी रकम बताओ फीस चार्ज कर रही थी जवानी दीवानी जलती जवानी होठों पर आज है प्यार की जैसे गीतों में उनके सेक्स अपील को देखा जा सकता है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता यह रकम हाथ में लिए अप्रूवल का इंतजार करते थे जिस-के चलते सिल्क के स्टारडम का आलम यह रहा कि महल 4 साल इंडस्ट्री में बिताने के साथ एक सिल्क करीब 200 फिल्मों में काम कर चुकी थी उन्होंने रजनीकांत का कमल हसन जैसे अभिनेताओं के साथ भी काम किया और कई बोल्ड सीन पर स्क्रीन पर किए। सिर्फ ने अपने जीवन के शर्मा भैया को कहीं दूर रख दिया था जिसके कारण फिल्मों में सॉफ्ट पोर्न अभिनेत्री भी उनको कहा जाने लगा अपने स्टारडम के चरणों पर सिल्क ने एक डॉक्टर से दूसरी शादी की उन्होंने सिर्फ को प्रोडक्शन में हाथ आजमाने के लिए कहा लेकिन उसमें सिर्फ को सफलता नहीं मिली और उनका सारा पैसा डूब के उसके बाद पत्नी ने भी उनसे धोखा किया पति से मिले धोखे के बाद वह शराब को ही अपना जीवन साथी समझने लगीं और जिंदगी बना दी सबसे दूर होती चली गई। 23 दिसंबर 1996 में महेश 36 साल की उम्र में चेन्नई स्थित अपार्टमेंट में उनकी डेड बॉडी पर कैसे लटकती मिली पुलिस में इस मामले को आत्महत्या का नाम देखकर फाइल को बंद कर दिया।

'इंडियन 2' ट्रेलर रिलीज के साथ ही छा गए कमल हासन

बहुप्रतीक्षित फिल्म 'इंडियन' की सीक्वल 'इंडियन 2' पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है। फिल्म के ट्रेलर में कमल हासन एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत रहे हैं।

कमल हासन अपनी आगामी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इन्हीं में एक नाम बहुप्रतीक्षित फिल्म ह्यइंडियनह्न की सीक्वल 'इंडियन 2' का है। फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। साथ ही अभिनेता 28 साल बाद वापस से स्वतंत्रता सेनानी के किरदार में लौटे हैं और भ्रष्टाचारियों का खात्मा करते नजर आए हैं। ट्रेलर में दिखी कहानी की झलक ने फिल्म के लिए फैंस के उत्साह को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ट्रेलर को देखने के बाद दर्शक गंभीर सामाजिक मुद्दों पर स्टाइलिश और भव्य व्यावसायिक मनोरंजन देने के लिए कमल हासन और निर्देशक शंकर की प्रशंसा कर रहे हैं।

हाई-ऑक्टेन थ्रिलर होगी 'इंडियन 2'

'इंडियन 2' के ट्रेलर में कमल हासन को अपने सिग्नेचर वर्मा कलाई मार्शल आर्ट के साथ आधुनिक स्टंट करते हुए दिखाया गया है, साथ ही भ्रष्टाचार पर केंद्रित एक बेहतरीन कहानी भी नजर आ रही है। एक्शन सीक्वेंस बड़े पैमाने पर और देखने में आश्चर्यजनक हैं, जो एक हाई-ऑक्टेन थ्रिलर का वादा करता है। फिल्म की कहानी वीरसेकरन सेनापति नामक एक स्वतंत्रता सेनानी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सिस्टम में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की हर संभव कोशिश करता है।

राजा हिंदुस्तानी से लेकर दिल तो पागल है तक... करिश्मा कपूर का बॉलीवुड सफर

90 के दशक के किसी भी बॉलीवुड प्रशंसक के लिए, करिश्मा कपूर का नाम कई यादें ताजा कर देता है, चाहे वह सिग्नेचर डांस स्टेप हो, डायलॉग्स हों या अभिनय। रणधीर कपूर और बबीता की बेटी, इस अभिनेत्री ने फिजा और जुबैदा जैसी फि ल्मों में अपने दमदार अभिनय से हम सभी को चकित कर दिया है। 90 के दशक के किसी भी बॉलीवुड प्रशंसक के लिए, करिश्मा कपूर का नाम कई यादें ताजा कर देता है, चाहे वह सिग्नेचर डांस स्टेप हो, डायलॉग्स हों या अभिनय। रणधीर कपूर और बबीता की बेटी, इस अभिनेत्री ने फिजा और जुबैदा जैसी फि ल्मों में अपने दमदार अभिनय से हम सभी को चकित कर दिया है। उनके 50वें जन्मदिन के अवसर पर, आइए उनकी कुछ लोकप्रिय फि ल्मों पर नजर डालते हैं, जिनमें उन्होंने दिखाया है कि वे जटिल किरदारों को भी सहजता से निभा सकती हैं।

1. राजा हिंदुस्तानी

राजा हिंदुस्तानी एक टैक्सी ड्राइवर राजा की कहानी है, जो एक अमीर लड़की आरती से प्यार करता है और उसके माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध उससे शादी कर लेता है। बाद में, उसकी सौतेली माँ जोड़े के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करती है। धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित इस फि ल्म में आमिर खान, कुणाल खेमू, अर्चना पूरन सिंह, जॉनी लीवर और सुरेश ओबेरॉय हैं।

2. हम साथ-साथ हैं

हम साथ-साथ हैं रामकिशन और ममता की कहानी है जो अपने तीन बेटों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब उनकी बेटी एक त्रासदी का सामना करती है, तो ममता अपने करीबी दोस्तों द्वारा उकसाई जाती है और अपने सौतेले बेटे विवेक के प्रति अपने दिल में कड़वाहट भर लेती है। सोराज बड़जात्या द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल और तब्बू जैसे कलाकार हैं।

3. हीरो नंबर 1

हीरो नंबर 1 एक अमीर व्यवसायी की कहानी है जो प्यार की खातिर घर के कामों में हाथ आजमाता है। राजू के रूप में, बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति, वह झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, खाना बनाता है, गाता है और नाचता है और अपनी प्रेमिका के करीबियों के दिलों में अपनी जगह बनाता है। डेविड धवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में गोविंदा, परेश रावल, कादर खान, टीकू तलसानिया और सतीश शाह हैं।

4. दिल तो पागल है

दिल तो पागल है एक डांस ट्रूप के निर्देशक राहुल की कहानी है, जिसकी एक सदस्य निशा उससे मन ही मन प्यार करती है। हालाँकि, वह पूजा की ओर आकर्षित हो जाता है, जिसकी अजय से सगाई हो चुकी है। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फि ल्म में माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, फरीदा जलाल और अरुणा ईरानी हैं।

5. मर्डर मुबारक

मर्डर मुबारक एक हत्या की जाँच की कहानी बताती है, एक गैर-पारंपरिक पुलिस अधिकारी संदिग्धों की एक श्रृंखला पर नजर डालता है। वह एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उनकी दुनिया में कदम रखता है, केवल यह जानने के लिए कि वहाँ जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है।

होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित इस फि ल्म में सारा अली खान, तारा अलीशा बेरी, विजय वर्मा, टिस्का चोपड़ा और पंकज त्रिपाठी हैं। इस बीच, काम के मोर्चे पर, करिश्मा को हाल ही में नेटफ्लिक्स की फि ल्म मर्डर मुबारक में पंकज त्रिपाठी, सारा अली खान और विजय वर्मा के साथ देखा गया था। वह अगली बार हेलेन और जीशु सेनगुप्ता के साथ ब्राउन नामक श्रृंखला में काम करेंगी।

मेडिकल कॉलेज में मरीजों की रही भीड़, उमस भरी गर्मी से मरीजों को हुई परेशानी

देवरिया(जीकेबी)। मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़ बढ़ी है। इसका व्यवस्था पर असर पड़ा। मरी-जों को एक से डेढ़ घंटे तक बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ी। कुछ जगह बगल से अंदर जाने को लेकर हो-हल्ला मचा। सुरक्षा कर्मियों व कर्मचारियों ने लोगों को शांत कराया। अल्ट्रासाउंड न होने से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी हुई।

महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में मरीज बढ़ गए हैं। शनिवार को अस्पताल खुलने पर मरीज पहुंचने लगे। सुबह आठ बजे से ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लाइन लग गई। इलाज के लिए 1934 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसके अलावा करीब 1500 से अधिक पुराने मरीज भी फालोअप के लिए पहुंचे थे। उनके साथ तीमारदार भी थे। पर्ची लेने के बाद लोग मरीज को लेकर ओपीडी में पहुंचे और कतार लगने लगी। सुबह 11 बजे तक मेडिसिन विभाग में लाइन लंबी रही। सुरक्षा कर्मी भीड़ को सहेजने में परेशान रहे। डॉ. गौरव, डॉ. सरफराज ने करीब 350 से अधिक मरीजों का इलाज किया। इसमें पेट दर्द, कमर के अधिक मरीज रहे। इसके अलावा अन्य बीमारी से पीड़ित मरीज थे। यहां लोगों को एक से डेढ़ घंटे इंतजार करना पड़ा। कतार में खड़े थककर कुछ लोग फर्श पर बैठ गए थे।

अस्पताल में भीड़ बढ़ी है। सभी को इलाज, जांच, दवा सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। लोगों को व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करने की जरूरत है। रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश से आने के बाद अल्ट्रासाउंड जांच की जाएगी। एक्स-रे मशीन में तकनीकी खराब को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं।

-डॉ. एचके मिश्रा,

मानसिक रोग विभाग में डॉ. अंबु पांडेय ने 110, चेस्ट व टीबी में डॉ. अनुराग शुक्ला, डॉ. ज्योति सिंह ने 102 मरीजों का इलाज किया। इसमें सांस के अलावा अन्य मरीज रहे। दंत में डॉ. रेनू सिंह, डॉ. प्रियंका, डॉ. निहारिका ने 72, कम्युनिटी मेडिसिन में 85 मरीजों का इलाज किया गया। चर्म रोग विभाग में डॉ. सुधा ने 180, सर्जरी में डॉ. राकेश कुमार, डॉ. ताहिर ने 102, नेत्र में डॉ. अदिती, डॉ. आकांक्षा, डॉ. दयानंद ने 225 मरीजों का इलाज किया। ईएनटी में मरीजों की लंबी लाइन रही। डॉ. प्रदीप गुप्ता ने 156 मरीजों का दोपहर 2:15 बजे तक इलाज किया। यहां बगल से जाने पर लोगों ने हो-हल्ला किया।

आर्थो में डॉ. अजय कुमार दूबे, डॉ. विकास मित्तल ने 445 से अधिक मरीजों का इलाज किया। यहां डॉक्टरों ने शाम करीब चार बजे तक सभी मरीजों का इलाज किया।

दवा काउंटर और जांच केंद्रों पर भी भीड़ रही। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। वेटिंग एरिया में फर्श पर बैठकर आराम कर रहे थे।

रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर रहने से ठप रहा अल्ट्रासाउंड

रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर जाने के कारण अल्ट्रासाउंड जांच नहीं हुई। मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ा। कुछ लोगों को निजी सेंटरों का सहारा लेना पड़ा। इसके लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ी।

मेडिकल कॉलेज के डिजिटल एक्स-रे सेंटर में शनिवार को जांच के बाद फिल्म नहीं दी गई।

इमेज ट्रांसफर न होने के कारण दिक्कत आई। मरी-जों को जांच की स्क्रीन से मोबाइल पर फोटो खींच कर रिपोर्ट दी गई। फोटो स्पष्ट न होने के कारण कुछ लोगों को परेशान होना पड़ा। जबकि छोटा मोबाइल होने के कारण करीब 15 लोगों को बिना जांच कराए लौटना पड़ा।

दोगुना मौतें, गर्मी से एक भी नहीं मानी गई

बस्ती(जीकेबी)। जिले में जैसे-जैसे तापमान बढ़ता गया, गर्मी जानलेवा साबित होती गई। गर्म हवा और तीखे तापमान की चपेट में आकर लोग जहां-तहां गिरकर मरते गए। कुछ की घरों में तबीयत बिगड़ी और जान चली गई। यही वजह रही कि मई की तुलना में जून में मौतों की संख्या में करीब दोगुना इजाफा हुआ। जून के सिर्फ 24 दिन में ही 77 शवों का पोस्टमार्टम हुआ। मगर, इनमें गर्मी से एक भी मौत नहीं मानी गई। कई मौतें तो ऐसी हुईं, जिनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। जिनके पोस्टमार्टम हुए उसकी रिपोर्ट में अंदरूनी अंगों का फेल होना कारण सामने आता है, इसलिए किसी में लू लगने की पुष्टि नहीं हुई।

जिले में मई के मध्य से उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी है। नौतपा के दौरान तो हालात और ही विपरीत हो गई, जब एक दिन में ही चार-पांच शव पोस्टमार्टम हाउस पहुंच रहे थे। नौतपा खत्म होने के बाद भी जानलेवा बनी गर्मी का कहर जारी है। मौसम की इसी मार के बीच पोस्टमार्टम हाउस में पिछले माह से लगातार शवों की संख्या बढ़ती जा रही है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।
संपादक: पंकज धर द्विवेदी
संपर्क सूत्र :
ghoonghatkibagawat37@gmail.com